रजिस्ट्री सं० डी (डी)-73 REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 1976/वैशाख 11, 1898
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 1976/VAISAKHA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1976

का० आ० 1519—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 13) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से, श्री रतीन्द्रनाथ सेनगुप्ता, सचिव, श्रम विभाग को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नाम निर्देशित करता है ।

[सं० 154/प० बं०/76]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 17th April, 1976

S.O. 1519—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of West Bengal, hereby nominates Shri Rathindra Nath Sengupta, Secretary, Labour Department, as the Chief Electoral Officer with effect from the date he takes charge of the office and until further orders

[No. 154/WB/76]

आदेश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1976

का० आ० 1520—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 265-मिर्जापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहम्मद अहमद, ग्राम लखनपुर, पत्रालय चील्ह, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

11GI/76—1

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोहम्मद अहमद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

आदेश से,

[सं० उ०प्र०-वि०स०/265/74(548)]

ए० एन० सैन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th April, 1976

S.O.1520.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohammad Ahmed, Village Lakhanpur, P. O. Chilh, District Mirzapur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 265. Mirzapur assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohammad Ahmad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/265/74 (548)]

A. N. SEN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंककारी विभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1976

आयकर

का० आ० 1521.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की सिफारिश पर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii) के अधीन अधिसूचना सं० 91 (फा० सं० 11/8/69-आयकर अधिनियम (ii) तारीख 7 जुलाई, 1969 द्वारा भारतीय शिक्षा उन्नयन संगम, मद्रास को दिया गया अनुमोदन 1 अप्रैल, 1976 से वापस लिया जाता है ।

[सं० 1231 (फा० सं० 203/4/76-आयकर अधिनियम II)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Banking)

New Delhi, the 17th February, 1976

INCOME-TAX

S.O. 1521.—It is hereby notified for general information that the approval given under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to Indian Association for the Advancement of Education, Madras by notification No. 91 (F. No. 11/8/69-ITA. II) dated 7th July, 1969 is withdrawn with effect from 1st April, 1976 on the recommendation of the prescribed Authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi.

[No. 1231 (F. No. 203/4/76-ITA. II)]

का०आ० 1522—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि अधिसूचना सं० 239 (फा० सं० 203/8/74-आई० टी० ए० 2) तारीख 9-8-1971 द्वारा एल० मदन मोहन आयुर्वेदिक रिसर्च सोसाइटी, दिल्ली को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii) के अधीन दिया गया अनुमोदन विहित प्राधिकारी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की सिफारिश पर 1-4-1976 से वापस लिया जाता है ।

[सं० 1232 (फा० सं० 203/7/76-आई० टी० ए० II)]

के० आर० राघवन, निदेशक

S.O. 1522.—It is hereby notified for general information that the approval given under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to L. Madan Mohan Lal Ayurvedic Research Society, Delhi by notification No. 239 (F. No. 203/8/71-ITA. II) dated 9th August, 1971 is withdrawn with effect from 1st April, 1976 on the recommendation of the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, new Delhi

[No. 1232 (F. No. 203/7/76-ITA. II)]

K. R. RAGHAVAN, Director

आयकर

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1976

का० आ० 1523—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि अधिसूचना सं० 763 (फा० सं० 203/36/74-आई० टी० ए० 2) तारीख 26-10-1974 द्वारा गुजरात अनुसंधान सोसाइटी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii) के अधीन दिया गया अनुमोदन, विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की सिफारिश पर 1-4-1976 से वापस लिया जाता है ।

[सं० 1235 (फा० सं० 203/133/75-आई० टी०ए०2)]

New Delhi, the 19th February, 1976

S.O. 1523.—It is hereby notified for general information that the approval given under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to Gujarat Research Society, Bombay by notification No. 763 (F. No. 203/36/74-ITA. II) dated 26-10-74, is withdrawn with effect from 1-4-76 on the recommendation of the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi.

[No. 1235 (F. No. 203/133/75-ITA. I]

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

का० आ० 1524—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि अधिसूचना सं० 566 (फा० सं० 203/15/73-आई० टी० ए० 2) तारीख 27 फरवरी, 1974 द्वारा कार्डिस लेबोरेटरीज, अहमदाबाद को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii) के अधीन दिया गया अनमोदन विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की सिफारिश पर 1-4-1976 से वापस लिया जाता है ।

[सं० 1241 (फा० सं० 203/149/75 आई०टी०ए० 2]

टी० जी० झुनझुनवाला, उपसचिव

New Delhi, the 23rd February, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 1524.—It is hereby notified for general information that the approval given under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to Cadila Laboratories, Ahmedabad, by notification No. 566 (F. No. 203/15/73-ITA. II) dated 27th February, 1974 is withdrawn with effect from 1st April, 1976, on the recommendation of the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi.

[No 1241 (F. No. 203/149/75-ITA. II)]
T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1976

का०आ० 1525—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्री वीरा नारायणपेरूमल मन्दिर कुरुलई, कवालप्पन डाकघर त्रिची जिला को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 1258 (फा० स० 176/53/75-आई० टी० ए० आई०)]
एम० शास्त्री, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 1976

S.O. 1525.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of section 80G of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Government hereby notifies Shri Veeranarayanaperumal Temple, Kurulai Kavalappan P. O. Trichy District to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said section.

[No. 1258 (F. No. 176/53/76-IT. AI)]
M. SHASTRI, Under Secy.

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1976

का०आ० 1526—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्ध पनिहाटी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर 31 मई, 1974 से 28 फरवरी, 1977 तक की अवधि के लिये लागू नहीं होंगे ।

[संख्या एफ० 8-11/76-ए०सी०]
हृषीकेश गुहा, अवर सचिव

(Banking)

New Delhi, the 15th April, 1976

S.O. 1526.—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act shall not apply to the Panihati Co-operative Bank Ltd; West Bengal for the period from 31st May, 1974 to 28th February, 1977.

[No. F. 8-11/76-AC]
H. K. GUHA, Under Secy.

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1976

स्टाम्प

का०आ० 1527.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, मुम्बई को, उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले पांच करोड़ रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचरों के प्ररूप में बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क मुद्दे प्रभार्य तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र के समेकित स्टाम्प शुल्क का संदाय करने की अनुज्ञा देती है ।

[सं० 19/76-स्टाम्प/फा०सं० 471/16/76-सीमा शुल्क-7]

(Revenue Wing)

ORDER

New Delhi, the 24th April, 1976

STAMPS

S.O. 1527.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Limited, Bombay to pay consolidated stamp duty of three lakhs and seventy five thousand rupees only chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of five crores of rupees to be issued by the said Corporation.

[No. 19/76-Stamps/F. No. 471/16/76-Cus.-VII]

आदेश

का०आ० 1528.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से जो गुजरात राज्य वित्त-निगम द्वारा जारी किए जाने वाले पांच सौ लाख रुपये मूल्य के वचन-पत्रों के रूप में तदर्थ बन्धपत्र उक्त के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती है ।

[सं० 20/76-स्टाम्प-एफ० स० 471/14/76-सीमा शुल्क-7]
डी० के० आचार्य, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1528.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the ad hoc bonds in the form of promissory notes to the value of five hundred lakhs of rupees to be issued by the Gujarat State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 20/76-Stamps/F. No. 471/14/76-Cus. VII]
D. K. ACHARYYA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1976

का० आ० 1529.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण मे मार्च 1976 के दिनांक 26 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इशू विभाग

देयताए	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
			सोने का सिक्का और बुलियन –		
बैंकिंग विभाग मे रखे हुए नोट	37,60,68,000		(क) भारत मे रखा हुआ	182,52,51,000	
संचलन मे नोट	6535,00,90,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतिया	271,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		6572,61,58,000	जोड		454,26,48,000
			रुपये का सिक्का		12,90,26,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतिया		6105 44 84 000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयताए		6572,61,58,000	कुल आस्तियां		6572,61,58,000

दिनांक . 30 मार्च, 1976

आर० के० हजारी, उप गवर्नर

26 मार्च 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताए	रुपये	आस्तिया	रुपये
चुकता पूजी	5,00,00,000	नोट	37,60,68,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	4,09,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छाटा सिक्का	7 54,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	175,59,99,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	563,24,16,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	विदेशो मे रखा हुआ बकाया*	1246,23,86,000
जमाराशियां		निवेश**	433,53,58,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम —	
(i) केन्द्रीय सरकार	660,52,90,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	.
(ii) राज्य सरकारें	9,99,27,000	(ii) राज्य सरकारो को‡	229,04,35,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम —	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	607,48,09,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंको को@	798,42,86,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	21,03,01,000	(ii) राज्य सरकारी बैंको को@@	359,68,41,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,75,96,000	(iii) दूसरो को	13,64,37,000
(iv) अन्य बैंक	80,05,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम —	
		(i) राज्य सरकारो को	75,28,97,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंको को	15,04,44,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको को	.
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का	94,60,00,000

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
(ग) अन्य	1611,83,95,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको के डिबेंचरो मे निवेश	10,11,46,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
देय बिल	147,20,94,000	राज्य सहकारी बैंको को ऋण और अग्रिम	84,60,60,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
अन्य देयताएं	970,57,62,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	382,60,58,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाडो/डिबेंचरो मे निवेश	..
		अन्य आस्तिया	530,81,85,000
रुपये	5050,21,79,000	रुपये	5050,21,79,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि मे से किये गये निवेश शामिल नही है ।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही है, परन्तु राज्य सरकारो को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल है ।

@भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको को मीयादी बिलो पर अग्रिम दिये गये 33,12,00,000 रुपये शामिल है ।

@@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही है ।

दिनांक 30 मार्च, 1976

आर० के० हजारी उप गवर्नर

[स० फ० 10/1)/76-बी० ओ०-I]

च० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

S.O. 1529.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 26th day of March, 1976.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department . . .	37,60,68,000		Gold Coin and Bullion :—		
			(a) Held in India . .	182,52,51,000	
Notes in circulation . .	6535,00,90,000		(b) Held outside India	..	
Total notes issued . . .		6572,61,58,000	Foreign Securities . .	271,73,97,000	
			TOTAL		454,26,48,000
			Rupee Coin . . .		12,90,26,000
			Government of India Rupee Securities . . .		6105,44,84,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
TOTAL LIABILITIES . . .		6572,61,58,000	TOTAL ASSETS . . .		6572,61,58,000

Dated the 30th day of March, 1976

R. K. HAZARI, Dy. Governor

New Delhi the 6th April, 1976

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 26th March, 1976

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	37,60,68,000
		Rupee Coin	4,09,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	7,54,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations Fund)	334,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:— (a) Internal	175,59,99,000
		(b) External	..
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	(c) Government Treasury Bills	563,24,16,000
		Balances Held Abroad*	1246,23,86,000
		Investments**	433,53,58,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	Loans and Advances to : (i) Central Government	..
		(ii) State Governments‡	229,04,35,000
Deposits:—		Loans and Advances to:—	
(a) Government :		(i) Scheduled Commercial Banks@	798,42,86,000
(i) Central Government.	660,52,90,000	(ii) State Co-operative Banks@ @	359,68,41,000
(ii) State Governments	9,99,27,000	(iii) Others	13,64,37,000
(b) Banks :		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund :	
(i) Scheduled Commercial Banks	607,48,09,000		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	21,03,01,000	(a) Loans and Advances to :—	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,75,96,000	(i) State Governments	75,28,97,000
(iv) Other Banks	80,05,000	(ii) State Co-operative Banks	15,04,44,000
(c) Others Bills Payable	1611,83,95,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
Other Liabilities	147,20,94,000	(iv) Agricultural Refinance & Development Corporation	94,60,00,000
	970,57,62,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,11,46,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	84,60,60,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund—	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	382,60,58,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	530,81,85,000
RUPEES	5050,21,79,000	RUPEES	5050,21,79,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

†Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

@Includes Rs. 33,12,000 advances to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

@ @ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

R. K. HAZARI Dy. Governor.

[F.No. 10(1)/76-BOI]

Dated the 30th day of March, 1976

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1976

का० आ० 1530.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर पर पालाकुझा ग्राम, मुवाट्टुपुझा ताल्लुक, जिला एर्नाकुलम, केरल राज्य में इसके द्वारा धारित 2.59 एकड़ अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में 5 अप्रैल, 1977 तक लागू नहीं होंगे।

[सं० 15(13)-बी०ओ० III/76)]

मे० भा० उसगावकर, अवर सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, the 6th April, 1976

S.O. 1530.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act, shall not apply till the 5th April, 1977, to the Catholic Syrian Bank Ltd., Trichur, in respect of the immovable property measuring 2.59 acres held by it at Palakuzha Village, Muvattupuzha Taluk, Ernakulam District, Kerala State.

[No. 15(13)-B.O. III/76]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1976

का० आ० 1531.—राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 35-क के उपबन्ध तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास पर लागू होंगे।

[संख्या एफ० 11-57/73-आई०एफ० II]

म० कृ० वेंकटाचलम्, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 8th April, 1976

S.O. 1531.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the State Financial Corporation Act, 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby directs that the provisions of section 35A of the said Act shall apply to the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited, Madras.

[No. F. 11-57/73-IF. II]

M. K. VENKATACHALAM, Jt. Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976

(आयकर)

का० आ० 1532.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अपनी अधिसूचना संख्या I (फा० सं० 55/233/63-आयकर) तारीख 18-5-64 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित वृद्धि करता है। उक्त अनुसूची में क्रम सं० 82 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी।

अनुसूची

क्रम सं०	व्यक्ति	आयकर अधिकारी	आयकर आयुक्त (अपील)	सहायक आयकर आयुक्त (अपील)	आयकर आयुक्त
1	2	3	4	5	6
83.1	ऐसे व्यक्ति जो भारत में अधिवसित नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति, जो अपने प्रस्थान के समय भारत में अधिवसित तो हो किन्तु आयकर प्राधिकारी की राय में भारत वापस लौटने का आशय नहीं रखते है और ऐसे व्यक्ति जिनका उससे पहले भारत में कहीं भी निर्धारण न हुआ हो और जिन्होंने आयकर अधिकारी, विदेश अनुभाग, पुणें को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230(1) के अधीन विहित प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दिया है।	आयकर अधिकारी विदेश अनुभाग पुणें	आयकर आयुक्त (अपील) पुणें, रेंज-1 पुणें	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) रेंज-1 पुणें	आयकर आयुक्त पुणें-1, पुणे

यह अधिसूचना 1-3-1976 से प्रभावी है।

[सं० 1240 (फा०सं० 187/11/75-आ०क० अ० I)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 21st February, 1976

(INCOME-TAX)

S.O. 1532 —In exercise of the powers conferred by Section 126 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following addition to the Schedule annexed to its Notification No. 1 (F No. 55/233/63-IT) dated 18-5-64 After S. No. 82 in the said Schedule, the following item shall be added.

SCHEDULE

S.No.	Persons	I.T.O.	I.A.C.	A.A.C.	C.I.T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
83.	1. Persons not domiciled in India and person who even if domiciled in India at the time of their departure have in the opinion of Income-Tax authority no intention of returning to India and persons who are not previously assessed anywhere in India and who apply for the certificate prescribed u/s 230(1) of the I.T. Act, 1961, to the I.T.O., Foreign Section, Poona.	ITO, Foreign Section, Poona.	IAC, Poona [Range-I, Poona.	AAC, Poona Range-I, Poona.	CIT, Poona-I, Poona.

2. This Notification shall take effect from 1-3-76.

[No. 1240(F.No.187/11/75-II.AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1976

आयकर

का० आ० 1533—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194-क की उपधारा (3) के खण्ड (iii) के उपखण्ड (च) के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त उपखण्ड के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करती है ।

1. मैसर्स अमृत लाल रावजी भाई पारेख, स्वामी, चन्द्राखण्ड अमृतलाल पारेख, बड़ौदा ।
2. मैसर्स अमृतलाल रावजी भाई पारेख, स्वामी मुकुन्दलाल अमृतलाल पारेख, नाडियाड ।
3. मैसर्स अमृतलाल रावजी भाई पारेख, स्वामी बालकृष्ण अमृतलाल पारेख, आनन्द ।

[सं० 1253 (फा० सं० 275/69/75-आई टी०जे०)]

के० आर० राघवन, निदेशक

New Delhi, the 11th March, 1976

INCOME TAX

S.O.1533.—In pursuance of the sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section 3 of Section 194A of the Income tax Act 1961, (43 of 1961) the Central Government hereby notifies the following persons for the purpose of the said sub-clause.

1. M/s. Amratlal Ravjibhai Parikh, Prop : Chandrakand Amratlal Parikh, Baroda.
2. M/s. Amratlal Ravjibhai Parikh, Prop : Mukundlal Amartlal Parikh, Nadiad.

M/s. Amratlal Ravjibhai Parikh, Prop : Balkrishna Amratlal Parikh, Anand.

[No. 1253 (F. No. 275/69/75-ITJ)]

K. R. RAGHAVAN, Dir.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

का० आ० 1534—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 230-ए की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करता है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे —

(क) कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी; और

(ख) केन्द्रीय, राज्य, अथवा प्रादेशिक अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित निगम ।

[सं० 27/1976/फा० सं० 358/8/74-आयकर (धनकर)]

एच० एन० मण्डल, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 1534.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 230A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby notifies that the provisions of sub-section (1) of the said section shall not apply to :—

(a) a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and

(b) a corporation established by or under a Central, State or Provincial Act.

[No. 27/1976/F. No. 358/8/74-IT(WT)]

H. N. MANDAL, Under Secy.

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरेट

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क पक्ष)

कोचीन, 22 जनवरी, 1976

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

का० आ० 1535.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस कलक्टरेट की अधिसूचना

सं० 3/67 तारीख 19 जनवरी, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करता हूं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, उसकी सारणी में क्रम सं० 55 के सामने स्तंभ 4 में, "विनिर्माण के सूत्र के अनुमोदन से संबंधित शक्ति", शब्दों के पश्चात् "और विनिर्माण करने वाले कारखाने से, प्राप्त करने वाले कारखाने तक उत्पाद शुल्क माल को ले जाने के लिए विहित समय सीमा बढ़ाने की शक्ति" शब्द जोड़े जाएंगे ।

[अधिसूचना सं० 1/76-सी०ई० सी० सं० (19) 30/29/75-सी एक्स 1]

एस० वेंकटराम अय्यर, कलक्टर

COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE (CENTRAL WING)

Cochin, the 22nd January, 1976

CENTRAL EXCISE

S.O. 1535.—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Central Excise Rules 1944, I hereby make the following amendment to this Collectorate Notification No. 3/67 dated the 19th January, 1967, namely :—

In the said Notification in the Table thereto, in Column 4 against serial No. 55, after the words, "All powers except the power in regard to the approval of formula of manufacture", the words, "and the power to extend the limit prescribed for conveying the excisable goods from the manufacturing factory to the receiving factory" shall be added.

[No. 1/76-CE. C. V (19) 30/29/75 CX. 1]

S. VENKATARAMA IYER, Collector.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1976

का० आ० 1536.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी, नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जूतों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :

1. (1) इन नियमों का नाम जूतों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जूतों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. अपील—(1) अभिकरण द्वारा नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देने से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा जिसमें तीन से कम और सात से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे ।

(2) पैनल में, विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी ।

(4) अपील, उसके प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी" ।

[सं० 6(5)/74/ई-आई०एण्ड ई०पी०]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 1st May, 1976

S.O. 1536.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Footwear (Inspection) Rules, 1967.

1. (1) These rules may be called the Export of Footwear (Inspection), Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Footwear (Inspection) Rules, 1967 for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel will consist atleast two-third of non-official of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt".

[No. 6(5)/74/EI&EP]

का० आ० 1537.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गम कराया का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :

1. (1) इन नियमों का नाम गम कराया का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गम कराया का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. अपील—(1) अभिकरण द्वारा नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देने से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए विशेषज्ञों के पैनल की अपील कर सकेगा जिसमें तीन से कम और सात से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे ।

(2) पैनल में विशेषज्ञों के पैनल का कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी ।

(4) अपील, उसके प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।"

[सं० 6(5)/74/ई० आई० एण्ड ई० पी०]

S.O. 1537.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection), Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of De-oiled Rice Bran (Inspection) Rules, 1966.

1. (1) These rules may be called the Export of De-oiled Rice Bran (Inspection) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of De-oiled Rice Bran (Inspection) Rules, 1966, for the rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three, but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel will consist of atleast two-third of on non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt".

[No. 6(5)/74/EI&EP]

S.O. 1538.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Gum Karaya (Inspection) Amendment Rules. 1966.

1. (1) These rules may be called the Export of Gum Karaya (Inspection) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Gum Karaya (Inspection) Amendment Rules, 1966, for rule 5, the following rules shall be substituted, namely :—

"5" "Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, wthin ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than threo but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel will consist of atleast two-third of non-official of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt".

[No. 6(5)/74/EI&EP]

का० आ० 1538.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी, नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1973 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल रहित चावल की भूसी का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है.

1. (1) इन नियमों का नाम तेल-रहित चावल की भूसी का निर्यात (निरीक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तेल रहित चावल की भूसी का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. अपील—(1) अभिकरण द्वारा नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन प्रमाण-पत्र देने से इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा, जिसमें तीन से कम और सात से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

(2) पैनल में, विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी।

(4) अपील, उसके प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी।

[सं० 6(5)/74/ई० आई० एण्ड ई० पी०]

आदेश

का० आ० : 1539.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केकड़े के डिब्बा-बंद मांस का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है,

अब यत: केन्द्रीय सरकार, उक्त उपनियम के अनुसरण में जनता की, जिसकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, सूचना के लिए उक्त प्रस्तावों को प्रकाशित करती है;

सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, भारत के निर्यात निरीक्षण परिषद् 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल) कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि केकड़े के डिब्बा-बंद मांस का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा;

(2) इस आदेश के उपाबन्ध-1 में दिए गए केकड़े के डिब्बा-बंद मांस के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को ऐसे प्रकार के निरीक्षण के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व केकड़े के डिब्बा-बन्द मांस को लागू होगा;

(3) इस आदेश के उपाबंध-II में दिए गए विनिर्देशों को केकड़े के डिब्बा-बंद मास के लिए मानक विनिर्देशों के रूप मे मान्यता देना, तथा

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान, केकड़े के डिब्बा-बंद मास के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसे केकड़े के डिब्बा-बंद मास का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण संबंधी शर्तों को पूरा करता है और वह निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को थल, समुद्र या वायु मार्गों द्वारा केकड़े के डिब्बा बंद मांस के नमूनों के निर्यात करने पर लागू नहीं होगी, परन्तु यह तब जब कि ऐसे नमूनों का जल-रहित शुद्ध भार 4 कि०ग्रा० से अधिक न हो।

3. इस आदेश में केकड़े के डिब्बा-बंद मास से लवण जल मे डिब्बा-बंद खाद्य केकड़े का मांस अभिप्रेत है।

उपाबन्ध-1

[पैरा 1 का उप-पैरा (2) देखिए]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अन्तर्गत बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

(1) संक्षिप्त नाम :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केकड़े के डिब्बा-बंद मांस निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 है।

(2) परिभाषाएं.—इन नियमों मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम, की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) 'केकड़े के डिब्बा-बंद मास' से लवण जल मे डिब्बा-बंद खाद्य केकड़े का मांस अभिप्रेत है।

(3) निरीक्षण का आधार.—निर्यात के लिए केकड़े के डिब्बा-बंद मास का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

(4) निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) केकड़े के डिब्बा-बंद मास के निर्यात का इच्छुक निर्यात-कर्ता निर्यात के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए अभिकरण के निकटतम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा जिससे वह ऐसे परेषण की यह देखने के लिए जांच कर सके या करवा सके कि क्या वह नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप है तथा निर्यात-कर्ता उसी समय ऐसी सूचनाओं की एक प्रति निर्यात निरीक्षण परिषद् के निकटतम कार्यालय को पृष्ठांकित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, निर्यातकर्ता के परिसर से परेषण के भेजने के प्रत्याशित समय से कम से कम 15 दिन पहले अभिकरण के कार्यालय में पहुंच जाएगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर अभिकरण, इस विषय मे निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार केकड़े के डिब्बा-बंद मांस के परेषण का निरीक्षण इस आशय से करेगा कि वह नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(4) निर्यातकर्ता अभिकरण को समस्त आवश्यक सुविधाएं देगा जिससे वह ऐसा निरीक्षण कर सके।

(5) निरीक्षण शुल्क.—निर्यात-कर्ता द्वारा पचास रुपए की न्यूनतम की सीमा में रहते हुए, अभिकरण को प्रत्येक परेषण के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से फीस, निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी।

(6) निरीक्षण का प्रमाणपत्र:— यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले केकड़े के डिब्बा-बन्द मांस का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यता-प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो अभिकरण, आवेदन के 15 दिन के भीतर, यह घोषित करते हुए प्रमाण-पत्र दे देगा कि केकड़े के डिब्बा-बंद मांस का परेषण, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण संबंधी शर्तों को पूरा करता है तथा वह निर्यात योग्य है।

परन्तु जहा अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है, वहा वह 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर देगा तथा इस प्रकार इन्कार किए जाने की सूचना उसके कारणो सहित निर्यात-कर्ता को देगा।

(7) अभिकरण, पोत-लदान, से पूर्व भण्डारकरण या अभिवहन के किसी भी स्थान पर निरीक्षण परेषण का ऐसा पर्यवेक्षण कर सकेगा। जो वह इन नियमो के प्रयोजन के समाधान के लिए आवश्यक समझे।

(8) अपील.—(1) निर्यात कर्ता नियम 6 के अधीन अभिकरण द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर देने पर, उसके द्वारा इन्कार की संसूचना प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त तीन से अन्यून किन्तु सात से अनधिक विशेषज्ञो के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल मे कम से कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील का निपटारा पन्द्रह दिनों के भीतर किया जाएगा।

उपाबन्ध-2

[पैरा 1, के उप-पैरा (3) देखिए]

डिब्बा-बंद केकड़े के मांस के लिए विनिर्देश

1. कच्ची सामग्री :

1. 1. डिब्बे में बंद करने के लिए मांस स्वस्थ, ताजे पकड़े हुए, जीवित एवं सख्त खोल वाले केकड़े का होगा।

2. डिब्बे.—

2. 1. केकड़े का मास को केवल टिकाऊ कागज या अच्छी क्वालिटी के चिकने कागज को अस्तर सहित भली प्रकार से प्रलाक्षित डिब्बे में पैक किया जाएगा।

2. 2. खोलने से पहले डिब्बों मे कम से कम 100 मि०मी० का खाली स्थान होगा।

2. 3. डिब्बा मे पिचकन, दिखाई देने वाला जंग या रिसाव नहीं होंगे।

3. लवण-जल.—

3. 1. लवण-जल हल्का-सा कोलायडीय होगा और 24 घंटे के लिए निम्न तापमान (4° सें०) पर भण्डारकरण किए जाने पर गाढ़ा नहीं होगा।

3. 2. लवण-जल में नमक की मात्रा 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4. पैकिंग .—

4. 1. केकड़े के शरीर का मांस और पंजे का मास मिलाया नही जाएगा और उन्हें क्रेता और विक्रेता के मध्य हुई संविदा के निबन्धनों की शर्तों के अनुसार परतो में पैक किया जाएगा। अन्यथा, पजों का मांस अलग-अलग परतो में सबसे ऊपर या सबसे नीचे पैक किया जाएगा।

4. 2. डिब्बे मे एक ही जाति के केकड़े का मांस पैक किया जाएगा।

5. जल-रहित भार :—

5. 1. प्रत्येक डिब्बे की सामग्री का जल-रहित भार, डिब्बे की कुल पानी की क्षमता के 65 प्रतिशत से कम नही होगा।

5. 2 मांस का जल-रहित भार, घोषित भार से कम नही होगा।

6. अभीनिन्द्रय क्वालिटी :—

6. 1. डिब्बे को खोलने पर उसमें भरी सामग्री में केकड़े के मांस की विशिष्ट रंग और गंध होगी और उससे कोई बाह्य गंध नही आएगी।

6. 2. सामग्री, ताजे पके हुए केकड़े के मांस की विशिष्ट गंध से भिन्न अन्य गंधों से तथा केकड़े के मांस मे भिन्न अन्य सामग्री मुक्त होगी।

6. 3. मास का रंग ऐसे नीले-पन लिए हुए नहीं होगा जो उसके खराब होने का संकेत करता है।

6. 4 पैक किए हुए डिब्बों मे, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमो के अधीन अनुज्ञात परिरक्षण एवं स्थिरक तत्व हो सकेंगे।

6. 5. डिब्बे की सामग्री में द्रवीकरण का कोई चिह्न नहीं होगा।

7. जीवाणु-विषयक क्रियाकलाप :—

7. 1. थियोग्लाइकोलेट सिस्टाइग्रैस ब्रोथ में चौबीस घंटों तक 37° से० पर उष्मायन के पश्चात् डिब्बे की सामग्री मे किसी प्रकार की वृद्धि नही होगी।

8. संकेतन :—

8. 1. डिब्बों पर जल-रहित भार, उत्पादक का नाम या उसकी फैक्ट्री का संकेतन विनिर्माण का वर्ष, मास तथा तारीख के अंकने समुद्भूत किए जाएंगे। डिब्बों पर संक्षिप्त रूप से समुद्भरण के लिए एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।

'5 एक्स वाई जेड
607 के'

इसमें :—

'5' पैक किए हुए मास के जल-रहित भार के लिए आता है।

'एक्स वाई जैड'—विनिर्माता के संक्षिप्त नाम या उसकी फैक्ट्री के संकेतन के लिए आता है।

'6'—विनिर्माण वर्ग के लिए आता है और इस उदाहरण मे यह सन् 1976 का संकेत करता है।

'07'—विनिर्माण के मास के लए आता है और इस उदाहरण मे यह जुलाई मास का संकेत करता है।

'क'—जुलाई मास के दौरान विनिर्माण की तारीख के लिए आता है।

[स० 6(21)/75-नि० नि० तथा नि०उ०]
के० वी० आलसुब्रमणियम, उप-निदेशक

S.O.1539.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), Canned Crab Meat should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required under sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby;

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this Order in the official Gazette to the Export Inspection Council of India, 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that Canned Crab Meat be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) to specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Canned Crab Meat (Inspection) Rules, 1976 set out in Annexure-I to this Order as the type of inspection which would be applied to such canned crab meat prior to export;

(3) to recognise the specifications as set out in Annexure-II to this Order as the standard specifications for canned crab meat; and

(4) to prohibit the export in course of international trade of canned crab meat unless the same is accompanied by a certificate issued by any one of the Export Inspection Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of such canned crab meat satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is export-worthy.

2. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of samples of canned crab meat to the prospective buyers, provided such samples do not exceed 4 kg. in nett drained weight.

3. In this Order "cannel crab meat" means meat of edible crabs canned in brine.

ANNEXURE-I

(See sub-paragraph (2) of paragraph 1)

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)

(1) Short title—These rules may be called the Export of Canned Crab Meat (Inspection) Rules, 1976.

(2) Definitions—In these rules nuless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) "agency" means any of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act;

(c) "Canned Crab Meat" means the meat of edible crabs canned in brine.

(3) Basis of inspection—Inspection of canned crab meat for export shall be carried out with a view to seeing that the canned crab meat conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

(4) Procedure of inspection—(1) An exporter intending to export canned crab meat shall submit an application to the nearest office of the agency giving particulars of the consignment intended to be exported to enable it to examine such consignment or cause the same to be examined to see whether the same conforms to the specifications referred to in rule 3 and the exporter shall at the same time endorse a copy of such intimations for inspection to the nearest office of the Export Inspection Council.

(2) Every application under sub-rule (1) shall reach the office of the Agency not less than 15 days before the anticipated time of despatch of the consignment from the exporter's premises.

(3) on receipt of the application referred to in sub-rule (2) the agency shall inspect the consignment of canned crab meat as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3.

(4) The exporter shall provide all necessary facilities to the agency to enable them to carry out such inspection.

5. Inspection fee—Subject to a minimum of rupees fifty for each consignment, a fee at the rate of 0.5 per cent of f.o.b. value, shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

6. Certificate of inspection—If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of caned crab meat to be exported complies with the requirements of the recognised specifications referred in rule 3, the agency shall, within 15 days of application issue a certificate declaring that the consignment of canned crab meat satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is export worthy.

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of 15 days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

7. The Agency may exercise such supervision of the inspected consignment at any place of storage or transit prior to its shipment as it may consider necessary for satisfying the purposes of these rules.

8. Appeal—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under rule 6, may, within three days of receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts, consisting of not less than three but not more than seven persons as may be appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days.

ANNEXURE—II

[See Sub-paragraph (3) of paragraph D]

SPECIFICATIONS FOR CANNED CRAB MEAT

1. RAW MATERIAL

1.1 The meat used for canning shall be obtained from healthy, freshly caught, live hard shelled crabs.

2. CANS

2.1 The crab meat shall be packed only in well lacquered cans with perchment paper lining or good quality grease paper lining.

2.2 The cans before opening shall have a minimum vacuum of 100 mm.

2.3 The cans shall not show flipper, panelling , rusting or swelling.

3. BRINE

3.1 The brine used shall be clear to slightly colloidal and shall not jell when stored at low temperature (4 degree C) for 24 hours.

3.2 The salt content of brine shall not exceed 2 per cent.

4. PACKING

4.1 The body meat and claw meat of the crab shall not be mixed and should be packed in layers, according to the terms of contract between the buyer and the seller. Otherwise, the claw meat shall be packed on top or at bottom in distinctly separate layers.

4.2 Only the meat of one species of crab shall be packed in one can.

5. DRAINED WEIGHT

5.1 The drained weight of the contents of each can shall not be less than 65 per cent of the nett water capacity of can.

5.2 The drained weight of the meat shall not be less than the declared weight.

6. ORGANOLEPTIC QUALITY

6.1 The contents of can on opening shall present a characteristic colour and odour of crab meat, and shall not display any foreign odour.

6.2 The material shall be free from any flavour other than the characteristic flavour of freshly cooked crab meat, and any foreign material other than crab meat.

6.3 The colour of the meat shall not be bluish, which is indicative of spoilage.

6.4 The packed cans may contain preservative and firming agents permitted under Prevention of Food Adulteration Rules.

6.5 The contents of can shall not show any sign of liquefaction.

7. BACTERIOLOGICAL ACTIVITY

7.1 The contents of the cans shall not show growth in thioglycollate cystine broth after 24 hours incubation at 37°C. The cans shall be incubated for a period of 7 days at 37°C before the contents are inoculated into thioglycollate broth.

8. CODING

8.1 The cans shall be embossed with markings of drained weight, name of the manufacturer' or factory code year, month and date of manufacture. An illustration for embossing the cans in the abbreviated form is given below:

'5XYZ
607K'

Wherein—

'5' stands for the drained weight of the meat packed;

'XYZ' stand for the name of manufacturer in the abbreviated form or his factory code;

'6' stands for the year of manufacture, and in this illustration it signifies the year 1976.

'07' stand for the month of manufacture, and in this illustration it signifies the month of July;

'K' stands for the date of manufacture during the month of July.

[No. 6(21)/75/EI&EP]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1976

का० आ० 1540.—भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (सहकारिता विभाग) के 2 जनवरी, 1974 के संकल्प संख्या पी-17011/1/74-टी० एड एम० के अनुसरण में और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय

(सहकारिता विभाग) की 30 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या टी-17011/1/74-प्रणि० तथा प्रबन्ध को रद्द करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष के परामर्श से श्री एम० एम० बागची, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लि० और श्री वीरशेट्टी कुशनूर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ को पहली अप्रैल, 1976 से 2 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्र स्तरीय सहकारी परिसंघों के उच्च प्रबंधकीय पदों के लिए 'नामिका प्राधिकरण' का सदस्य नामित करती है ।

[संख्या पी-17011/1/74-एल० एंड एम०]

टी० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 5th April, 1976

S.O. 1540.—In pursuance of the Resolution No. P-17011/-1/74-T&M dated the 2nd January, 1974 of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Deptt. of Cooperation) and in supersession of the notification of the Govt. of India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Cooperation) No. P-17011/1/74-T&M dated the 30th March, 1974 the Central Government hereby nominates, in consultation with the President National Cooperative Union of India, Shri M. M. Bagchi, President National Cooperative Consumers Federation Lt. and Shri Veershetty Kashnoor, Chairman, All India State Cooperative Banks Federation as Members of the Panel Authority for top management posts of National level Cooperative Federation for a period of two years from 1st April, 1976.

[No. P. 17011/1/74-L&M]

T. BALAKRISHNAN, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1976

का०आ० 1541:—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का पदनाम (1)	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग (2)
1 सिविल इंजीनियर साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, साम्भर झील (राजस्थान)	1. रावणटिब्बा व्हाइट गेट को जाने वाला मार्ग ।
	2 व्हाइट गेट के निकट खाई ।
	3. दवलानी को जाने वाली नमक पगडण्डी ।
	4. छ-टाइप बारामासी क्वार्टर ।
	5 उद्यान ।
	6. रावणटिब्बा कालोनी ।
	7. नमक बंगले और सलग्न नौकरों के क्वार्टर ।
	8 कालोनी को जाने वाला मार्ग ।
	9. खुली भूमि ।
	10. नौकरों के क्वार्टर ।
	11. बागान भूमि ।
	12 रावणटिब्बा के बाहर पक्की दीवार ।
	13. रावणटिब्बा के बाहर बेध कुआ ।
	14. वर्ग 4 कर्मचारिवृन्द क्वार्टर्स ।
	15. झापोग कर्मचारिवृन्द कालोनी ।
	16. झापोग श्रमिक कालोनी ।
	17. साम्भर बिजली घर को जाने वाली नमक पगडण्डी ।
	18. केन्द्रीय भण्डार सं० 8 पगडण्डी ।
	19. केन्द्रीय भण्डार स० 7 पुल से मेन लाइन गेट तक मार्ग ।
	20 मेन लाइन 2' गॉज ट्रैक ।
	21 खारी भूमि ।
	22. वैद्युत कर्मचारिवृन्द क्वार्टर भूमि ।
	23 केन्द्रीय भण्डार 6 और 7 के मध्य की पगडण्डी जो केन्द्रीय भण्डार 8 तक जाती है ।
	24 अधीक्षक, विक्रय का कार्यालय ।
	25 बिजली घर ।
	26 मेन लाइन गेट से रेल गेट तक जाने वाला मार्ग, जो साम्भर नगर तक जाती है ।
	27 केबिन संग्राही के निकट खारी भूमि बिटर्न भण्डार ।
	28. कर्मचारिवृन्द कालोनी किंगस्क्वायर ।
	29. रेलवे स्टेशन से रावणटिब्बा व्हाईट गेट तक का मार्ग ।
	30. केन्द्रीय भण्डार स० 1 पगडण्डी ।
	31. केन्द्रीय भण्डार सं० 1 प्लेटफार्म ।
	32. केन्द्रीय भण्डार सं० 2 और 3 प्लेटफार्म।
	33. अधीक्षक, विक्रय बंगले ।
	34. राइफल रेंज ।
	35. नया उद्यान भूमि ।
	36. अधीक्षक नया बंगला ।
	37 नया के लिपिक और निरीक्षक के क्वार्टर ।
	38. अधीक्षक, गुधा का बंगला ।
	39. केन्द्रीय भण्डार 4 दक्षिण ओर की भूमि ।
	40. गुधा के समीप भूमि ।
	41. खाल पीर की डुगरी ।
	42. खेजरी गगल ।
2. सक्षम प्रबन्धक, हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, खारगोधा, गुजरात ।	1. विनिर्मित नमक के लिए नमक उद्योगशाला क्षेत्र, जिसमें लवणजल गर्तों के लिए प्रयुक्त भूमि सम्मिलित है, और जिसमें नमक उद्योगशाला में चौकियों, ऊडू मोतीसारी आदि में भवनों, के अधिभोगाधीन क्षेत्र भी है ।

(1)	(2)
	2 नमक के विनिर्माण और विक्रय से अनुषंगी भूमि जैसे कि रेल-पार्श्व, केन्द्रीय भण्डार और कर्मशाला आदि ।
	3. आवासीय प्रयोजनों अर्थात् भवनों, सड़कों, उद्यानों, खेल के मैदानों, तालाबों, खले क्षेत्र आदि के लिए प्रयुक्त भूमि ।
	4. मकान आदि के निर्माण के लिए प्राइवेट दलों को पट्टे पर दिए गए प्लाट जिसमें अधिक्रमणों के अधीन क्षेत्र भी है ।
	5. बंजर भूमि ।
	6. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के सर्वेक्षण संख्या 242 पर के, सारे भवन ।
	7. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के प्लाटों जो उन्हें सर्वेक्षण स॰ 242 में पट्टे पर दिए गए है पर के सारे प्राइवेट भवन ।

[फा॰ सं॰ 43028/15/74-साल्ट]

ज॰ ज॰ राजाध्यक्ष, उप सचिव

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 20th April, 1976

S.O. 1541.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of gazetted officers of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act, within the limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises
(1)	(2)
1. The Civil Engineer, Sambhar Salts Limited, Sambhar Lake (Rajasthan)	1. Road to Rawantiha white-gate.
	2. Ditch near whitegate.
	3. Salt track to Deodani.
	4. G. type Baramasi quarters.
	5. Garden.
	6. Rawantiba colony.
	7. Salt Bungalows & attached servants' quarters.
	8. Road to Colony.
	9. Open land.
	10. Servant's quarters.
	11. Plantation land.
	12. Pucca wall outside Rawantiba.
	13. Bore well to Rawantiba.
	14. Class IV staff quarters.
	15. Jhapog staff colony.
	16. Jhapog Labour colony.
	17. Salt track Jhapog to Sambhar Power House.
	18. Central Stores No. 8 track.
	19. Road from C.S. 7 bridge to Main Line gate.
	20. Main Line 2' gauge track
	21. Saline land.
	22. Elect. staff quarters land
	23. Track between C.S. 6 & 7 leading to C.S.8.
	24. Supdt. Sales Office.
	25. Power House.
	26. Road from Main line Gate to Rly. gate leading to Sambhar city.
	27. Saline land bittern store near cabin condensor.
	28. Staff colony Kingsquare.
	29. Road from Rly. Station to Rawantiba white gate.
	30. Central Stores No. 1 track.
	31. Central Stores No. 1 platform.
	32. Central Stores No. 2 & 3 Platform.
	33. Supdt. Sales Bungalow.
	34. Rifle range.
	35. Nawa Garden land.
	36. Supdt. Nawa's bungalow.
	37. Clerk & Inspector's quarters at Nawa.
	38. Supdt. Gudha's bungalow.
	39. Central Stores 4 South side land.
	40. Gudha vicinity land.
	41. Lal Pir Ki Doongri.
	42. Khejri Jungle.
2. The Works Manager, Hindustan Salts Ltd. Kharaghoda, Gujarat.	1. Area of salt works for salt manufactured including lands used for brine pits including areas occupied by chowkies, buildings at Udoo, Motisari etc. in the salt works.
	2. Lands incidental to manufacture and sales of salt such as Railway siding, Central Stores and workshop etc.
	3 Lands utilized for residential purposes i.e. for buildings, roads, gardens, play-grounds, tanks, open areas etc.
	4. Plots leased out to private parties for constructing houses etc. including areas under encroachment.
	5. Waste lands.
	6. All buildings belonging to Hindustan Salts Ltd. on S.No. 242
	7. Private buildings on Hindustan Salts Ltd. plots leased out to them on Survey No. 242,

[File No. 43028/15/74-Salt]

J. G. RAJADHYAKSHA, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1976

का० आ० 1542.—विशाखापत्तनम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का कतिपय प्रारूप, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मन्त्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 5086, तारीख 14 नवम्बर 1975 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 29 नवम्बर, 1975 के पृष्ठ 4156–57 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी।

और उक्त राजपत्र 17 दिसम्बर, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था, और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. विशाखापत्तनम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खंड 3 के उपखंड (त) में, "350 टन" अंकों और शब्द के पश्चात्, "या किसी टन भार के लैश पोत से विसर्जित लैश बजरा" शब्द जोड़े जाएंगे।

[सं० एल० डी० वी०/24/75-I]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 19th April, 1976

S.O. 1542.—Whereas certain draft scheme further to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 4156-57 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 29th November, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 5086 dated the 14th November, 1975 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 17th December, 1975;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central ernment;

erefore, in exercise of the powers conferred by (1) of section 4 of the said Act, the Central ereby makes the following scheme further to sakhapatnam Dock Workers (Regulation of mendment Scheme, 1959, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-clause (p) of clause 3 of the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, after the figures and word "350 tons" the words "or lash barge, discharged from LASH ship, of any tonnage" shall be added.

[No. LDV/24/75-I]

का० आ० 1543.—विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का कतिपय प्रारूप, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 5087 तारीख 14 नवम्बर, 1975 के अधीन, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii), तारीख 29 नवम्बर, 1975 के पृष्ठ 4157 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी।

और उक्त राजपत्र 17 दिसम्बर, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 के खंड 3 के उपखंड (ठ) में, "350 टन" अंकों और शब्द के पश्चात् "या किसी टन भार के लैश पोत से विसर्जित लैश बजरा" शब्द जोड़े जाएंगे।

[एल डी वी/24/75–II]

वी० संकालिंगम, अवर सचिव (एल)

S.O. 1543.—Whereas certain draft scheme further to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 4157 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 29th November, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S.O. 5087 dated the 14th November, 1975 inviting objections and suggestions

from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 17th December, 1975;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Scheme may be called the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment, Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-clause (l) of clause 3 of the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, after the figures and word "350 tons" the words "or Lash barge, discharged from LASH ship, of any tonnage" shall be added

[No. LDV/24/75-II]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1976

का० आ० 1544.—नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०आ० 2565 दिनांक 18-6-1975 के अतिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा नाविक भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड के परामर्श से और प्रशासनिक व्यय लेखे में अधिशेष पर विचार करते हुए पहली अप्रैल, 1976 से उक्त योजना के पैरा 35 के अधीन देय प्रशासनिक व्यय 1.75% नियत करती है।

[एम डब्ल्यू एस (19)/76-एम टी]

दीवान चन्द अहीर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th April, 1976

S.O. 1544.—In exercise of the powers conferred by paragraph 37 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2565, dated 18-6-1975, the Central Government, in consultation with the Board of Trustees of the seamen's Provident Fund and considering the surplus in the Administrative Charge Account, hereby fixes, with effect from the 1st April, 1976, the administrative charge payable under paragraph 35 of the said Scheme, at 1.75 per cent.

[No. MWS(19)/76-MT]

D. C. AHIR, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1976

का० आ० 1545.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि उन भूमियों से जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, कोयला अभिप्राप्त किए जाने की सम्भाव्यता है,

अतः, अब, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उनमें कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखाक का निरीक्षण, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में या उप आयुक्त, हजारीबाग के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सब व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सब मानचित्र, चार्ट और अन्य दस्तावेजें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को परिदत्त कर देंगे।

अनुसूची

ब्लाक I और IV विस्तारण

रामगढ़ कोयला क्षेत्र

डी आर जी० सं० राजस्व/69/75

तारीख 24-11-75

(इसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि वर्णित की गई है)

उपब्लॉक 'क' ब्लॉक I का विस्तारण

क्रम संख्या	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोयद्वारा	रामगढ़	150	हजारी बाग		भाग
2.	लरही टोंगरी	,,	151	,,		,,
3.	जनिमामारा	,,	152	,,		,,

1	2	3	4	5	6	7
4.	गौराबेरा	रामगढ़	153	हजारीबाग		भाग
5.	भुचुंगडीह	,,	154	,,		,,
6.	सेवाई	,,	155	,,		,,

कुल क्षेत्र : 600.00 एकड़ (लगभग) या 242.80 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा, गोपो और कोयहारा ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और यहीं दामोदर नदी की केन्द्रीय रेखा का भाग बनती है ।

ख-ग-घ-ङ-च रेखाएं, कोयहारा, गौराबेरा, सेवाई और भुचुंगडीह ग्रामो मे से जाती है जो कि कोयला अधिनियम की धारा 9 के अधीन अर्जित रामगढ़ ब्लॉक I की पूर्वी सीमा का भाग भी बनती है ।

च-छ-ज-झ रेखाएं भुचुगडीह, जनिग्रामारा, लरही टोंगरी ग्रामो में से जाती है और, कोयहारा और लरही टोंगरी ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है ।

झ-ञ रेखा, गोपो और कोयहारा ग्रामों की सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है जो कि दामोदर नदी की केन्द्रीय रेखा का भाग भी बनती है ।

ञ-ट-क रेखाए कोयहारा गांव में से होकर आरम्भिक बिन्दु 'क' से जा मिलती है ।

उपब्लॉक –ख ब्लॉक I का विस्तारण

क्रम संख्या	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1.	भुचुंगडीह	रामगढ़	154	हजारीबाग		भाग

कुल क्षेत्र : 28.00 एकड़ (लगभग)
या 11.33 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :

ट-ड-ढ-ण रेखाएं, भुचुंगडीह ग्राम मे से जाती है ।

ण-त रेखा, भुचगडीह ग्राम में से जाती है ।

त-थ रेखा, भुचुगडीह और बान्दा ग्रामों की सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है, जो कि बेराह नदी की केन्द्रीय रेखा का भाग भी बनती है ।

थ-ट रेखा भुचुगडीह ग्राम में से जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'ट' से जा मिलती है ।

उप-ब्लॉक ग ब्लॉक I का विस्तारण

क्रम संख्या	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1.	सेवाई	रामगढ़	155	हजारीबाग		भाग
2.	हुटुगदाग	,,	156	,,		,,
3.	तेवारदाग	,,	158	,,		,,

कुल क्षेत्र : 90.00 एकड़ (लगभग)
या 36.42 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :

द-ध-न रेखाए, सेवाई और हुटुगदाग ग्रामों मे से जाती है जो कोयला अधिनियम की धारा 9 के अधीन अर्जित रामगढ़ ब्लॉक-I की सामान्य सीमा और भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र की उत्तरी सीमा का भाग भी बनती है ।

न-प रेखा, हुटुगदाग, तेवारदाग ग्रामो में से जाती है जो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र की पूर्वी सीमा का भाग भी बनती है ।

प-फ रेखा, तेवारदाग और हुटुगदाग और सेवाई ग्राम में से जाती है जो कोयला अधिनियम की धारा 9 के अधीन अर्जित रामगढ़ ब्लॉक-I की दक्षिणी सीमा का भाग भी बनती है और आरम्भिक बिन्दु 'द' से जा मिलती है ।

उपब्लॉक-ष ब्लॉक I का विस्तारण

क्रम संख्या	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1.	सानरी	रामगढ़	157	हजारीबाग		भाग
				कुल क्षेत्र :	55.00 एकड़ (लगभग)	
				या	22.25 हेक्टेयर (लगभग)	

सीमा वर्णन

ख-भ रेखा, सानरी ग्राम में से जाती है जो कि भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भी भाग बनती है।

भ-म रेखा, सानरी ग्राम में से जाती है।

म-ब रेखा, सानरी ग्राम में से जाती है जो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भी भाग बनती है और आरम्भिक बिन्दु 'ब' में जा मिलती है।

उपब्लॉक-ङ ब्लॉक I से IV का विस्तारण

क्रम संख्या	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1.	माएल	रामगढ़	143	हजारीबाग		भाग
2.	सेवाई	रामगढ़	155	हजारीबाग		भाग
				कुल क्षेत्र :	535.00 एकड़ (लगभग)	
				या	216.50 हेक्टेयर (लगभग)	

सीमा वर्णन

क'-ख' रेखा, माएल और सेवाई ग्रामों में से जाती है।

ख'-ग'-घ' रेखाएं, सेवाई ग्राम में से जाती हैं जो कि भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा और कोयला अर्जित क्षेत्र की सामान्य सीमा और कोयला अधिनियम की धारा 9 के अधीन अर्जित रामगढ़ ब्लॉक I की सामान्य सीमा का भाग बनती है।

घ'-ङ'-क' रेखाए माएल और सेवाई ग्रामों की सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ जाती हैं और फिर माएल ग्राम से होकर जाती है जो कि कोयला अधिनियम की धारा 9 के अधीन अर्जित रामगढ़ ब्लॉक IV की सामान्य सीमा का भाग बनती है और आरम्भिक केन्द्र 'क' से जा मिलती है।

[सं० 19(11)/76—सी०ई० एल०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 7th April, 1976

S.O. **1545**.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi or at the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Blocks I & IV Extensions

Ramgarh Coalfield

Drg.No.Rev/69/75
Dt. 24-11-75
(Showing lands notified for prospecting)

Sub-Block—A

Extn. of Block-I

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1.	Koihara	Ramgarh	150	Hazaribagh		Part
2.	Lerhi-Tongri	,,	151	,,		,,
3.	Janiamara	,,	152	,,		,,
4.	Gaurabera	,,	153	,,		,,
5.	Bhuchungdih	,,	154	,,		,,
6.	Sewai	,,	155	,,		,,
				Total area:	600.00	acres (approx.)
				or	242.80	hectares (approx.)

Boundary description :

A–B line passes along the part common boundary of villages Gopo & Koihara which also forms part Central line of River Damodar.

B-C-D-E-F lines pass through villages Koihara, Gaurabera, Sewai and Buchungdih which also forms part eastern boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9 of the Coal Act.

F–G–H–I lines pass through villages Bhuchungdih, Janiamara, Lerhi Tongri and along part common boundary of villages Koihara & Lehri Tongri.

I–J line passes along the part common boundary of villages Gopo & Koihara which also forms part Central line of River Damodar.

J–K–A lines pass through villages Koihara and meets at starting point 'A'.

Sub-Block—B

Extn. of Block-I

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bhuchungdih	Ramgarh	154	Hazaribagh		Part
				Total area:	28.00 acres (approx.)	
				or	11.33 hectares (approx.)	

Boundary description :

L–M–N–O lines pass through village Bhuchungdih.

O–P line passes through village Bhuchungdih.

P–Q line passes along part common boundary of villages Bhuchungdih and Banda which also forms part central line of Verah Nadi.

Q–L line passes through village Bhuchungdih and meets at starting point 'L'.

Sub-Block–C

Extn. of Block–I

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sewai	Ramgarh	155	Hazaribagh		Part
2.	Hutugdag	,,	156	,,		,,
3.	Tewardag	,,	158	,,		,,
				Total area :	90.00 acres (approx.)	
				or	34.42 hectares (approx.)	

Boundary description :

R–S–T lines pass through villages Sewai and Hutugdag which also forms part common boundary of Ramgarh Block-I acquired u/s 9 of the Coal Act and part northern boundary of the area acquired under L.A. Act.

T–U line passes through villages Hutugdag, Tewardag which also forms part eastern boundary of area acquired under L.A. Act.

U–V line passes through village Tewardag and Hutugdag.

V–R line passes through village Hutugdag and Sewai which also forms part southern boundary of Ramgarh Block-I acquired u/s 9 of the Coal Act and meets at starting point 'B'.

Sub-Block—D

Extn. of Block–I

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sanri	Ramgarh	157	Hazaribagh		Part

Total area : 55.00 acres (approx.)
or 22.25 hect. (approx.)

Boundary description :

W–X line passes through village Sanri which also forms part common boundary of the area acquired under L.A. Act.

X–Y line passes through village Sanri.

Y–W line passes through village Sanri which also forms part common boundary of the area acquired under L.A. Act and meets at starting point 'W'.

Sub-Block—E

Extn. of Block I & IV

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1.	Mael	Ramgarh	148	Hazaribagh		Part
2.	Sewai	,,	155	,,		,,

Total area 535.00 acres (approx.)
or 216.50 hect. (approx.)

Boundary description :

A^1–B^1 line passes through villages Mael & Sewai.

B^1–C^1–D^1 lines pass through village Sewai which also forms part common boundary of the area acquired under L.A. Act and part common boundary of Ramgarh Block I acquired u/s 9 of the Coal Act.

D^1–E^1–A^1 lines pass along part common boundary of villages Mael & Sewai and again through village Mael which also forms part common boundary of Ramgarh Block IV acquired u/s 9 of the Coal Act and meets at starting point 'A'.

[No. 19(11)/76-CEL]

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1976

का० आ० 1546.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमियों से कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है;

अतः, अब, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उनमें पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची, बिहार में या कलक्टर के कार्यालय, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में या कोयला कन्ट्रोलर के कार्यालय, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध समस्त व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी मानचित्र, चार्ट और अन्य दस्तावेज इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को परिदत्त कर देंगे ।

अनुसूची

दुधिचुवा ब्लाक-II

सिंगरौली कोयला वाला क्षेत्र

(उत्तर प्रदेश)

रेखांक सं. राजस्व/66/क/75

तारीख 21-11-75

(इसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि वर्णित की गई है)

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	तहसील सं०	थाना	परगना	जिला क्षेत्र	टिप्पण
1.	परकावार राजा	दुधी	34	भिखरा (खैरवा)	सिंगरौली	मिरजापुर	भाग
2	जोगीचौरा	,,	46	,,	,,	,,	,,
3.	चिलकादार	,,	49	,,	,,	,,	,,
4.	कोटा	,,	82	,,	,,	,,	,,
5.	खैरिया	,,	115	,,	,,	,,	,,
6.	भेरखा	,,	—	,,	,,	,,	,,

कुल क्षेत्र : 3500.00 एकड़ (लगभग)

या 1416.38 हेक्टेयर्स (लगभग)

सीमा वर्णन :—

घ-ङ	रेखा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है (जो उत्तर प्रदेश के चिल्कादांर ग्राम के साथ तथा मध्य प्रदेश के सरसोबा राजा टोला, सरसोबा लाल टोला ग्रामों के साथ और चन्देली ग्राम के भाग के साथ सामान्य सीमा का भाग भी है) और बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।
ङ-ञ	रेखा चिल्कादांर, कोटा, खरिया और परसवार राँजा ग्रामों से होकर जाती है- और 'ञ' बिन्दु पर मिलती है।
ञ-ट	रेखा परसवार राजा, जोगीचौरा और भैरवारा ग्राम से होकर जाती है और बिन्दु 'ट' पर मिलती है।
ट-छ	रेखा भैरवारा और भामसिला ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है (जो कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित जोगीचौरा ब्लॉक की सामान्य सीमा का भाग भी है) और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।
छ-च	रेखा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सामान्य सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है (जो उत्तर प्रदेश के भैरवा, खारिया और चिलकादांर ग्रामों के साथ तथा मध्य प्रदेश के दुधिचुवा ग्राम के साथ सामान्य सीमा भी है) और आरम्भिक बिन्दु 'च' पर मिलती है।

[सं० 19(19)/76-सैल]

एस० आर० ए० रिजवी, उप-सचिव

New Delhi, 13th April, 1976

S.O. 1546.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the areacovered by this notification can be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar) or at the office of the Collector, Mirzapur (Uttar Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Revenue Officer Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi within 90 days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE
Dudhichuwa Block-II
Singrauli Coalfield
(Uttar Pradesh)

Drg.No.Rev/66/A/75
Dated 21-11-75
(showing lands notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Tahsil	Tahsil No.	Thana	Pargana	Distt.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6		7	
1.	Parsawar Raia	Dudhi	34	Misra (Khairwa)	Singrauli	Mirzapur	Part	
2.	Jogichowra	,,	46	,,	,,	,,	,,	
3.	Chilkadanr	,,	49	,,	,,	,,	,,	
4.	Kota	,,	82	,,	,,	,,	,,	
5.	Kharia	,,	115	,,	,,	,,	,,	
6.	Bhairwa							

Total area : 3500.00 acres (approximately)
or 1416.38 hectares (approximately)

Boundary description :

F–I	line passes along the part common boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh (which also forms part common boundary with the village Chilkadanr of Uttar Pradesh and with the villages Sarsoba Raja Tola; Sarsopa Lal Tola and part of village Chandeli of Madhya Pradesh) and meets at point 'I'.
I–J	line passes through villages Chilkadanr, Kota, Kharia and Parswar Raja and meets at point 'J'.
J–K	line passes through village Parsawar Raja, Jogichowra and Bhairwa and meets at point 'K'.
K–G	line passes along the part common boundary of villages Bhairwa and Jamsila [which also forms part common boundary of Jogichawara Block acquired u/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development Act, 1957] and meets at point 'G'.
G–F	line passes along the part common boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh (which also forms common boundary with the villages of Bhairwa, Koaria and Chilkadanr of Uttar Pradesh and with the village of Dudhichuwa of Madhya Pradesh) and meets at starting point 'F'.

[No. 19(10)/76-CEL]

S. R. A. RIZVI, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल 1976

का० आ० 1547.—भारतीय चिकित्सा परिषद् (इलेक्शन आफ लाइमेंसिएट्स) नियमावली, 1965 के नियम 2 के खंड (घ) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग की 7 फरवरी 1975 की अधिसूचना संख्या 4-16/71-एम०पी०टी० का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा०पी०एन०घई, स्वास्थ्य सेवा सहायक महानिदेशक (एम), नई दिल्ली को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन भारतीय चिकित्सा परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन कराने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या वी० 11013/3/76-एम०पी०टी०]

एस० श्रीनिवासन, उप-सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 19th April, 1976

S.O. 1547.—pursuance of clause (d) of rule 2 of the Indian Medical Council (Election of Licentiates) Rules, 1965, and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Planning, Deptt. of Health, No. 4-16/71-MPT, dated the 7th February, 1975, the Central Government hereby appoints Dr. P. N. Ghei, Assistant Director General of Health Services(M), New Delhi as the Returning Officer for the conduct of election of members to the Medical Council of India under clause (d) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).

[No. V. 11013/3/76-MPT]

S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1976

शुद्धि पत्र

का० आ० 1548 —इस विभाग के तारीख 12 सितम्बर, 1975 के आदेश सं० 52/8/73-एफ०सी०-3 (खंड 4) में निम्नलिखित शुद्धियां की जाएं :—

आदेश में क्रम संख्या	की जाने वाली शुद्धि
24	स्तम्भ 2 में "श्री अमरनाथ" के स्थान पर "श्री अमरनाथ सूरी" पढ़ें।

[सं० 52/8/73-एफ०सी०-3 खंड-5]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

New Delhi, the 1st April, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 1548.—In this Department Order No. 52/8/73-III (Vol. IV), dated 12-9-1975, the following corrections shall be carried out :

Sl. No. in the Order	*Correction to be carried out.*
24	For the words "Shri Amarnath" in col. 2 read "Shri Amarnath Suri".

[No. 52/8/73-FC-III(Vol.-IV)]

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1976

का० आ० 1549.—इस विभाग के तारीख 24 सितम्बर, 1974 के आदेश संख्या 52/21/68 अप्रो०स्था० 1/एफ० सी० 3 में निम्नलिखित शुद्धियां की जाएं :—

आदेश में क्रम संख्या	की जाने वाली शुद्धि
109	क्रम संख्या 96 को ध्यान में रखते हुए इसे काट दें।
490	स्तम्भ 2 में "श्री ए० शिवशंकर" के स्थान पर "श्री ए० शिवशंकर तावकर" पढ़ें।
851	स्तम्भ 2 में "श्री एम० वी०कृष्णराव" के स्थान पर "श्री के०वी०कृष्ण राव" पढ़ें।
2804	स्तम्भ 2 में "श्री एम०राजू वेलू" के स्थान पर "श्री के०राजवेल" पढ़ें।
2876	स्तम्भ 2 में "श्री डी०दोरई रामू" के स्थान पर "श्री डी० दोरई कन्नू" पढ़ें।

[सं० 52/8/73-एफ०सी०-3 खंड-5]

डी० कृष्णमूर्ति, उप-सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st April 1976

S.O. 1549.—In this Department Order No. 52/21/68-REI/FC-III, dated 24-9-1973, the following corrections shall be carried out

Sl. No. in the Order	*Correction to be carried out*
109	May be deleted in view of Sl. No. 96.
490	For the words "Shri A. Sivasankar" in col. 2 read "Shri A. Sivasankar Tawker".
851	For the words "Shri M. V. Krishna Rao" in column 2 read "Shri K. V. Krishna Rao".
2804	For the words "Shri M. Raju Velu" in col. 2 read "Shri K. Rajavel".
2876	For the words "Shri D. Dorai Ramu" in col. 2 read "Shri D. Doraikannu"

[No. 52/8/73-FC-III(Vol., V)]

D. KRISHNAMURTI, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1976

का० आ० 1550.—दार्जिलिंग टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिये जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (III) (बी बी) में अपेक्षित है। दार्जिलिंग मे चालू समाचार पत्रो मे निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हे कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हो तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनो के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 1-1-76 को दैनिक 'बासुमति' और 'विश्वमित्र' कलकत्ता और 3-1-76 को अमृत बाजार पत्रिका और युगान्तर कलकत्ता, दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नही हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III)(बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-5-1976 से दार्जिलिंग का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

दार्जिलिंग टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :—

दार्जिलिंग का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जोकि दार्जिलिंग नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में पड़ता है;

किन्तु वे टेलीफोन उपभोक्ता जो कि दार्जिलिंग नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हे दार्जिलिंग टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करते रहेंगे।

[संख्या 3-15/74-पी एच बी]

(DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS)

(P & T Board)

New Delhi, the 7th April, 1976

S.O. 1550.—Whereas a public notice for revising the local area of Darjeeling Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Darjeeling, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 1st January 1976 in daily Newspapers 'Basumati' and 'Vishwamitra' Calcutta and on 3rd January 1976 in daily Newspapers 'Amrit Bazar Patrika' and 'Jugantar' Calcutta.

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-5-76 the revised local area of Darjeeling shall be as under;

Darjeeling Telephone Exchange System

The local area of Darjeeling shall cover an area falling under the jurisdiction of Darjeeling Municipality :

Provided that the telephone subscribers located outside Darjeeling Municipal limit but who are served from Darjeeling Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-15/75-PHB]

का० आ० 1551.—सोनाडा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(III) (बी बी) में अपेक्षित है सोनाडा मे चालू समाचार पत्रो मे निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करे।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 1-1-76 को वसुमति और विश्वमित्र और 3-1-76 को अमृत बाजार पत्रिका और युगान्तर कलकत्ता, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई थी।

उक्त सुचना के उत्तर में जनसाधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III)(बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-5-1976 से सोनाडा का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

सोनाडा टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :—

सोनाडा का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जोकि सोनाडा टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि० मी० की अरीय दूरी के अंतर्गत पड़ता है:

किन्तु उत्तर में यह सीमा पेशोक रोड़ और सुखिया पोखरी रोड़ तक सीमित होगी।

[संख्या 3-15/74-पी एच बी]

S.O. 1551.—Whereas a public sector for revising the local area of Sonada Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Sonada, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 1st January, 1976 in daily Newspapers 'Basumati' and 'Vishwamitra', Calcutta and on 3rd January 1976 in daily Newspapers 'Amrit Bazar Patrika' and 'Jugantar', Calcutta;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-5-76 the revised local area of Sonada shall be as under;

Sonada Telephone Exchange System

The local area of Sonada shall cover an area falling within 5 Kms radial distance from 'Sonada Telephone Exchange;

Provided that in the North this limit shall be restricted to Peshok Road and Sukhiapokhri Road.

[No. 3-15/74-PHB]

का० आ० 1552.—टकडाह टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(III) (बी बी) में अपेक्षित है टकडाह मे चालू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हो तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 1-1-76 को बसुमति और विश्वमित्र और 3-1-76 को अमृत बाजार पत्रिका और युगान्तर कलकत्ता दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III) (बी बी) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-5-1976 से टकडाह का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

टकडाह टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था —

टकडाह का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जोकि टकडाह टेलीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के अंतर्गत पड़ता है.

किन्तु यह सीमा पश्चिम में दार्जिलिंग टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि० मी० अरीय दूरी की लाइन तक प्रतिबंधित होगी।

[संख्या 3-15/74-पी एच बी]

S.O. 1552.—Whereas a public notice for revising the local area of Takdah Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Takdah, inviting objectons and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspaper.

And whereas the said notice was made available to the public on 1st January 1976 in daily Newspapers 'Basumati' and 'Vishwamitra' Calcutta and on 3rd January 1976 in daily Newspapers 'Amrit Bazar Patrika' and 'Jugantar' Calcutta;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-5-76 the revised local area of Takdah shall be as under ;

Takdah Telephone Exchange System

The local area of Takdah shall cover an area falling within 5 Kms. radial distance from Takdah Telephone Exchange :

Provided that in the West this limit shall be restricted to the line of 5 Kms. radial distance from Darjeeling Telephone Exchange.

[No. 3-15/74-PHB]

का० आ० 1553.—विजनवाडी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र मे बदली किये जाने की बाबत जिस लोगो पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (III) (बी बी) में अपेक्षित है विजनवाडी मे चालू समाचार पत्रो में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हो तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 1-1-76 को बसुमति और विश्वमित्र और 3-1-76 को अमृत बाजार पत्रिका और युगान्तर कलकत्ता दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नही हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III) (बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-5-76 से विजनवाडी का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

विजनवाडी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :—

विजनवाडी का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जोकि विजनवाडी टेलीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के अंतर्गत पड़ता है :

किन्तु यह सीमा दक्षिण में दार्जिलिंग टेलीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर की अरीय दूरी पर प्रतिबंधित होगी।

[संख्या 3-15/74-पी एच बी]

S.O. 1553.—Whereas a public notice for revising the local area of Bijonbari Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Bijonbari, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 1st January 1976 in daily Newspapers 'Basumati' and 'Vishwamitra' Calcutta and on 3rd January 1976 in daily Newspapers 'Amrit Bazar Patrika' and 'Jugantar' Calcutta;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-5-1976 the revised local area of Bijonbari shall be as under;

Bijonbari Telephone Exchange System

The local area of Bijonbari shall cover an area falling 5 Kms. radial distance from Bijonbar Telephone Exchange :

Provided that in the South this limit shall be restricted to the line of 5 Kms. radial distance from Darjeeling Telephone Exchange.

[No. 3-15/74-PHB]

का० आ० 1554.—सुखियापोखरी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक पब्लिक नोटिस उन सब की जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(III) (बी बी) में अपेक्षित है सुखियापोखिरी में प्रचलित समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हे कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनो के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त नोटिस सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 1-1-76 को बसुमति और विश्वमित्र और 3-1-76 को अमृत बाजार पत्रिका और युगान्तर कलकत्ता दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था।

उक्त नोटिस के उत्तर मे जनसाधारण की ओर से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नही हुए है।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III) (बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है कि 1-5-76 से सुखियापोखरी का संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा —

सुखियापोखरी टेलीफोन एक्सचेज व्यवस्था :—

सुखियापोखरी का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि सुखियापोखरी टेली-फोन एक्सचेज से 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर पडता है।

[संख्या 3-15/74-पी एच बी]

S.O. 1554.—Whereas a public notice for revising the local area of Sukhiapokhri Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Sukhiapokhri inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 1st January 1976 in daily Newspapers 'Basumati' and 'Vishwamitra' Calcutta and on 3rd January 1976 in daily Newspapers 'Amrit Bazar Patrika' and 'Jugantar' Calcutta;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-5-76 the revised local area of Sukhiapokhri shall be as under ;

Sukhiapokhri Telephone Exchange System

The local area of Sukhiapokhri shall cover an area falling within 5 Kms. radial distance from Sukhiapokhri Telephone Exchange.

[No. 3-15/74-PHB]

का० आ० 1555 —नगरिसपुर टेलीफोन एक्सचेज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र मे बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक पब्लिक नोटिस उन सब की जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(III) (बी बी) मे अपेक्षित है नगरिसपुर में प्रचलित समाचार पत्रो में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हो तो वे नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त नोटिस सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 1-1-76 को बसुमति और विश्वमित्र और 3-1-76 को अमृत बाजार पत्रिका और युगान्तर कलकत्ता दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित कराया गया था।

उक्त नोटिस के उत्तर मे जनसाधारण की ओर से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III) (बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है कि 1-5-76 से नगरिसपुर का संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

नगरिसपुर टेलीफोन एक्सचेज व्यवस्था :—

नगरिसपुर का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि नगरिसपुर टेलीफोन एक्सचेज से 5 किलोमीटर अरीय दूरी के भीतर पडता है, किन्तु पूर्व में यह सीमा कुरसियोंग टेलीफोन एक्सचेंज और सोनाडा टेलीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर अरीय दूरी तक की लाइन तक प्रतिबंधित होगी।

[संख्या 3-15/74-पी एच बी]

प्रा० ना० कौल, निदेशक

S.O. 1555.—Whereas a public notice for revising the local area of Nagrispur Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Nagrispur, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 1st January 1976 in daily Newspapers 'Basumati' and 'Vishwamitra' Calcutta and on 3rd January 1976 in daily Newspapers 'Amrit Bazar Patrika' and 'Jugantar' Calcutta :

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-5-76 the revised local area of Nagrispur shall be as under ;

Nagrispur Telephone Exchange System :

The local area of Nagrispur shall cover an area falling within 5 Kms. radial distance from Nagrispur Telephone Exchange ;

Provided that in the East this limit shall be restricted to the line of 5 Kms radial distance from Kurseong Telephone Excange and Sonada Telephone Excange.

[No. 3-15/74-PHB]

P. N. KAUL., Director

(P & T Directorate)

New Delhi, the 19th April, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 1556.—The existing words "Arni in Tamil Nadu circle" published in Gazette of India, part II section 3 subsection (2) on 28-2-76 under S.O. No. 911 should be substituted by the following : "Vidisha in M.P. Circle".

[No. 5-5/76-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Dir.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1976

का० आ० 1557 —राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में, नासिक, कोयम्बेटूर, कोरेटी, अलीगढ़ नीलोखेड़ी, सतरागाछी (हावड़ा), रिंग रोड, नई दिल्ली, फरीदाबाद और गंगटोक में स्थित भारत सरकार मुद्रणालय मे नियोजित अधिकारियो को सरकारी निवासो का आबंटन नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम नासिक, कोयम्बेटूर, कोरेटी, अलीगढ़, नीलोखेड़ी, संतरागाछी (हावड़ा), रिंग रोड, नई दिल्ली, फरीदाबाद और गंगटोक में स्थित भारत सरकार मुद्रणालय में नियोजित अधिकारियो को सरकारी निवासों का आबंटन (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 नासिक, कोयम्बेटूर, कोरेटी, अलीगढ़, नीलोखेड़ी, संतरागाछी (हावड़ा), रिंग रोड, नई दिल्ली, फरीदाबाद और गंगटोक में स्थित भारत सरकार मुद्रणालय में नियोजित अधिकारियों को सरकारी निवासों का आबंटन नियम, 1972 में—

(i) परिचायक पैरा में, "मुद्रण और लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक" शब्दों के स्थान पर, "मुद्रण निदेशालय" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) नियम 6 के उपनियम (iii) में, "उपनियम (i)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपनियम (i)(क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(iii) नियम 9 में, सारणी के नीचे 'स्पष्टीकरण' में.—

(क) पैरा (i) में,—

(i) कोष्ठक और अंक "(i)" का लोप किया जाएगा;

(ii) "मद (iv) और (v)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "सारणी की मद (iv) और (v)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) "प्रभार त्याग करने की तारीख" शब्दों और चिह्न के पश्चात् "उक्त सारणी की," शब्द जोड़े जाएंगे;

(ख) पैरा "(2)" को पैरा "(iii)" के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) पैरा 3 का लोप किया जाएगा।

(घ) पैरा (4) को पैरा "(iv)" के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

(iv) अनुसूची में, "6 केयरटेकर" प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"7. कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत)"।

[फा०सं० 1/23/68-पी० II (जिल्द-II)]

धन राज, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 13th April, 1976

S.O. 1557.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences to officers employed in Government of India Press located at Nasik, Coimbatore, Koratty, Aligarh, Nilogheri, Santragachi (Howrah), Ring Road, New Delhi, Faridabad and Gangtok Rules, 1972, namely :—

1. (i) These rules may be called the Allotment of Government Residences to officers employed in Government of India Press, located at Nasik, Coimbatore, Koratty, Aligarh, Nilokheri, Santragachi (Howrah), Ring Road, New Delhi, Faridabad, and Gangtok (Amendment) Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residences to officers employed in Government of India Press located at Nasik, Coimbatore, Koratty, Aligarh, Nilokheri, Santragachi (Howrah), Ring Road, New Delhi, Faridabad and Gangtok Rules, 1972—

(i) in the introductory paragraph, for the words "Chief Controller of Printing and Stationery to offices" the words "Directorate of Printing to officers" shall be substituted.

(ii) in sub rule (iii) of rule 6, for the words, figure and brackets "sub-rule (1)(a)", the words, figure and brackets "sub-rule (i)(a)" shall be substituted.

(iii) in rule 9, in the 'Explanation' below the Table—

(a) in paragraph (1),—

(i) the brackets and figure "(1)" shall be omitted;

(ii) for the expression "items (iv) and (v)", the expression "items (iv) and (v) in the Table" shall be substituted;

(iii) the words "of the said Table" shall be inserted at the end;

(b) in paragraph 2, for the bracket and figure "(2)", the bracket and figure "(ii)" shall be substituted.

(c) paragraph (3) shall be omitted;

(d) paragraph (4) shall be re-numbered as "(iv)".

(iv) in rule 18, the entry "(i)" shall be inserted before the entry "If an officer to whome a residence has been allotted....."

(v) In the Schedule, the following serial number and entry shall be inserted after the entry "6. Caretaker", namely :—

"7. Junior Engineer (Electrical)".

[F. No. 1/23/68-PII(Vol. II)]

DHAN RAJ, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1976

का० आ० 1558.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ओरिएण्टल अग्नि और साधारण बीमा कं० के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ओरिएण्टल अग्नि और साधारण बीमा कं० के प्रबन्धतंत्र का, अपने कर्मकारों को पहले से ही संदत्त कृत्रिम भत्तों का वापस लेना और अनुग्रहपूर्वक संदाय की वसूली करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[संख्या एल०-17011/2/75-डी०-2/ए]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 17th January, 1976

S.O. 1558.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Oriental Fire and General Insurance Company and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

THE SCHEDULE

Whether the management of Oriental Fire and General Insurance Company is justified in withdrawing the functional allowance and in recovering the ex-gratia payment already paid to their workmen? If not, to what relief are the said workmen entitled?

[No. L-17011/2/75/DII/A]

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1976

का० आ० 1559 केन्द्रीय सरकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 7 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4106 तारीख 30 नवम्बर, 1972 मे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची मे :—

(i) क्रम संख्या 8 के सामने, स्तम्भ 3 मे, "आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्य" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"आन्ध्र प्रदेश राज्य और कर्नाटक राज्य (बगलौर, कोलार, मैसूर, माण्डया, टुमकुर, कुर्ग, दक्षिणी कनारा, हसन, चिकमगलूर, शिमोगा और चित्रदुर्ग के सिविल जिलो को छोड़ कर),"

(ii) क्रम संख्या 11 के सामने, स्तम्भ 3 में, "तमिलनाडु और केरल राज्य तथा पाडिचेरी, लक्काद्वीव मिनिकोय और अमिनदीवी द्वीप," प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"तमिलनाडु और केरल राज्य तथा कर्नाटक राज्य के बगलौर, कोलार, मैसूर, माण्डया, टमकुर, कुर्ग, दक्षिणी कनारा, हसन, चिकमगलूर, शिमोगा और चित्रदुर्ग के सिविल जिले और पाडिचेरी और लक्षद्वीप के सघ राज्य क्षेत्र।"

[सं० एस०-70025/1275-एफ०पी०जी०]

New Delhi, the 21st April, 1976

S.O. 1559.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 7 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4106 dated the 30th November, 1972 namely :—

In the Schedule to the said notification :—

(i) against serial number 8, in column 3, for the entry "The States of Andhra Pradesh and Mysore" the following entry shall be substituted namely :—

"The State of Andhra Pradesh and the State of Karnataka (excluding the civil districts of Bangalore, Kolar, Mysore, Mandya, Tumkur, Coorg, South Kanara, Hassan, Chickmagulur, Shimoga and Chitradurga);"

(ii) against serial number 11, in column 3, for the entry "The States of Tamil Nadu and Kerala and the Union territories of Pondicherry, Laccadive, Minicoy and Aminidivi Islands.", the following entry shall be substituted namely :—

"The States of Tamil Nadu, Kerala and the civil districts of Bangalore, Kolar, Mysore, Mandya, Tumkur, Coorg, South Kanara, Hassan, Chickmagulur, Shimoga and Chitradurga of the State of Karnataka and the Union territories of Pondicherry and Lakshadweep."

[No. S-70025/12/75-FPG]

का० आ० 1560—केंद्रीय सरकार, उपदान संदाय अधिनियम 1972 (1972 का 39) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4107 तारीख 30 नवम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 26, 30 और 31 के सामने, स्तम्भ 3 मे, "मैसूर", शब्द के स्थान पर, "कर्नाटक," शब्द रखा जाएगा।

[संख्या एस०-700 25/1275-एफ०पी०जी०]

आर० कुजीथापदम, उप सचिव

S.O. 1560.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4107, dated the 30th November, 1972, namely :—

In the Schedule to the said notification, against serial numbers 26, 30 and 31 in column 3 for the word "Mysore", the word "Karnataka" shall be substituted.

[No. S-70025/12/75-FPG]

R. KUNJITHAPADAM, Dy. Secy.

नई दिल्ली, तारीख 20 अप्रैल, 1976

का० आ० 1561—चामनाला कोयला खान (बिहार राज्य मे धनबाद जिला) मे 5 अप्रैल 1976 को जनहानि करने वाली दुर्घटना हो गई है;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि दुर्घटना के कारणो और परिस्थितियो के बारे मे विधिवत् जांच होनी चाहिए;

अत, अब, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री उज्जलनारायण सिन्हा, पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, को ऐसी जांच करने के लिए नियुक्त करती है और निम्नलिखित व्यक्तियो को उक्त जांच मे असैसर के रूप में नियुक्त भी करती है, अर्थात् :—

1 श्री सी० करुणाकरण, सेवानिवृत्त महानिदेशक, ज्युआलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया फ्लैट नं० 2 सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट क्वार्टर्स, बैलवेदर, अलीपुर, कलकत्ता-27।

2. श्री जी० एस० मरवाहा, निदेशक, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद।

3. श्री दामोदर पाण्डे, संसद सदस्य, सचिव, कोलियरी मजदूर संघ, डाकघर भुरकुण्डा कोलियरी, जिला हजारीबाग, बिहार।

[सं०ज०-11015/9/75-एम०-I]

जे० सी० सक्सेना, अवर सचिव

New Delhi, the 20th April, 1976

S.O. 1561.—Whereas an accident occurred in the Chasnala Colliery (District Dhanbad in the State of Bihar) on the 5th April, 1975 causing loss of lives;

And whereas the Central Government is of opinion that a formal inquiry into the causes of and circumstances attending the accident ought to be held;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Justice Ujjal Narain Sinha, retired Chief Justice of the Patna High Court, to hold such enquiry and also appoints the following persons as assessors in holding the enquiry, namely :—

1. Shri C. Karunkaran, Retired Director General of Geological Survey of India, Flat No. 2, Central Government Quarters, Belvedore, Alipore, Calcutta-27.

2. Shri G. S. Marwaha, Director, Indian School of Mines, Dhanbad.

3. Shri Damodar Pandey, M.P., Secretary, Colliery Mazdoor Sangh, P.O. Bhurkunda Colliery, Distt. Hazaribagh, Bihar.

[No. N-11015/9/75-MI]

J. C. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1976

का० आ० 1562.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार को श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4522 तारीख 29 सितम्बर 1975 द्वारा यूरेनियम उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 अक्तूबर, 1975 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा-2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 अप्रैल, 1976 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस०-11017/4/76-डी०-1 ए]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 20th April, 1976

S.O. 1562.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4522 dated the 29th September, 1975 the services in the uranium industry, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 29-10-75.

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 29th April, 1976.

[No. S-11017/4/76/DIA]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

New Delhi, the 23rd April, 1976

S.O. 1563.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of 4-B Quarry of Bhowra Colliery of M/s. Bhowra Kankanee Collieries Co. Ltd. P. O. Bhowra, Dist. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 20-4-1976.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 46 of 1969

Presiding Officer : Shri S. N. Johri, B.Sc., LL.M.

PARTIES:

Employers in relation to 4-B Quarry of Bhowra Colliery of M/s. Bhowra Kankanee Collieries Co. Ltd. P.O. Bhowra, Distt. Dhanbad.

AND

Their workmen represented by the Khan Mazdoor Congress.

APPEARANCES:

For Employers—Shri T. P. Chowdhury, Advocate.

For Workmen—Shri B. Lal, Advocate.

Industry : Coal State : Bihar

Dhanbad, the 12th April, 1976

AWARD

This is a reference made by the Govt. of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. 2/21/69-LRII dated 16-7-1969 under Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 projecting the following question for adjudication by this Tribunal :

"Whether the existing scales of pay given to the workmen engaged in excavation work in 4-B Quarry of the management of Bhowra Colliery of Messrs Karamchand Thapar and Brothers (P) Ltd., P. O. Bhowra, (Dhanbad) require revision? If so, to what relief are they entitled?"

2. It is not disputed that in 4-B quarry of Bhowra Colliery north mechanised working was introduced for excavation work in the year 1964. Probably that was the only market colliery which had N.C.D.C. type of mechanised working. At first this mechanised working was arranged through the contractors M/s. Mechanised Mining Corporation and M/s. Hindustrips Mining Corporation. Subsequently in the year 1964 itself M/s. Bhowra Kankanee Collieries Ltd. (owners) and M/s. Karmchand Thapar and Brothers (P) Ltd. (Managers) took up the mechanised work-

ing departmentally and absorbed all the employees of the contractor working on the machines etc. The wages as paid by the contractors were continued to be paid by the company. On 20-12-64 the wages were revised by the company and again with effect from 1-11-65 as a consequence to the agitation launched by Colliery Mazdoor Sangh. A third revision took place with effect from 15 8-67 from which date Wage Board recommendations were suitably implemented. While so revising the grades this time the management did not simply convert the existing grades and scales to the convertible Wage Board scale but it took the job description and nature of machines into consideration as was meant for N.C.D.C. collieries where mechanised working was in vogue. This resulted in downward revision of categories. Initially V.D.A. was given as per Wage Board recommendations but subsequent increases in VDA as per rise in price index was not given regularly.

3. Following chart will show the revision of the scales that were made by the management from time to time:

Job name	Contractor Rates (1964)	Revised on 20-12-64	Revised on 1-11-65	Revised since 15-8-67
(1) Shovel Operator	6-0.50-8	7-0.50-9	7-0.50-9	12-0.60-18
(2) Dumper Operator	2.75-0.25-4	3.50-0.25-4.50	4.75-0.37-6.25	10.75-0.40-14.75
(3) Dozer Operator	-do-	-do-	5.25-0.37-6.75	-do-
(4) Drill OPerator	-do-	3.27-4.41	3.50-0.25-4.50	-do-
(5) Fitter				
(i) Motor Singh Cat. VII	1.86-0 14-2.71	Continued the same	3 50-3.50-0.25-4.50	10 75-0.40-14.75
(ii) Surath Singh	1. 19-0.08-1.67	1.25-1.34-1.47-1.52-1.01.70-1.79	1.18-0. 14-2.71	7.95-0.28-10.75 Cat. V
(iii) Sukhdeo Chauhan	1.06-0.03-1.24	-do-	1.25-0.09-1.79	6.90-0.20-8.90 Cat. IV
(iv) Abdul Mannan	71.50-3.64-93.34	85-5.00-115	123 Basic+67 DA	327-60 Basic
(6) Tripman/Dumpman	1.06-0.03-1.24 VDA was paid:	1.06-0.03-1.24 @0.78 per day from 15-8-67 @1.11 " " " 15-9-69 @1.29 " " " 1-10-69	2.25-0.12-2.62	

4. Management's case is that N.C.D.C. was not a comparable concern being a public sector organisation. It was not obligatory to implement wage Board recommendations in full. The question of D.A. is not within the compass of the reference. V.D.A. at the rate 1.29 was paid from 1-10-69 in terms of the settlement between the management and the union. Wage increase was given in the light of the job description and the type and capacity of the machine handled. Hence wages do not require any revision whatsover.

5. The case of the workmen is that there could be no distinction between N.C.D.C. and the market company in the matter of payment of wages as the jobs were identical. The two concerns were comparable units. The management took certificate on the declaration that it had implemented Wage Board recommendations hence it was now too late in the day to say that it was not obligatory to implement Wage Board recommendations. V.D.A. should have been paid regularly according to the rise in price index. The workmen demand that they should have been fixed as follows:—

Sl. No.	Designation	Grade in Wage Board recommendations for N.C.D.C.	Category	Adjustment in new scale and fixation on 15-8-67
(1)	Excavator Operator (Shovel Operator) Grade I	16.00-0.90-25.00	A	16.90+10%
(2)	Dumper Operator Grade I	12.00-0.60-18.00	C	12.60+10%
(3)	Dozer Operator	13.50-0.70-20.50	B	14.20+10%
(4)	Drill Operator Grade I	—do—	B	—do—
(5)	Excavation Plant Fitter Grade I	—do—	B	—do—
(6)	Tripman/Dumpman	7.95-0.08-10.75 (Category V daily rated)	F	8.23+10%

6. At the time of arguments the point that the N.C.D.C. was not a comparable unit was not pressed and it was conceded by the management that it had given a declaration that it implemented Wage Board recommendatons generally even though the recommendations were obligatory to be implemented. Thus after factual implementaion in principle there was no point in saying that it was not obligatory to implement the recommendations.

7. Shovel Operators (Excavator Operators)

According to Appendix VII of Wage Board recommendations Vol. II page 55 Excavator Operators are of two grades namely Grade I and Grade II. Whereas Grade I operator should be a man of 7 years experience and should be operating shovels of 4-4-1/2 cubic yard capacity, Grade II operators are required to have only 3 years experience and should be handling not less than 2-1/2 cubic yard capacity shovels In the present case the machanised working started in 1964 hence upto 15-8-67 they had hardly an experience of 3 years and according to Autar Singh MW-1 they are handling shovels of 2-1/2 - 3-1/2 cu.yds capacity. They are thus rightly placed in Grade II and have been rightly given the wages of C Category in the scale of 12.00-0.60-18.00.

8. Dumper Operators

Similarly at page 56 there are two grades of Dumper Operators. While Grade I requires 5 years experience and handling of not less than 22 tons capacity dumpers, Grade II requires only 2 years experience and handling of 15 ton capacity dumpers. In the present case as discussed above, the expcience was only of about 3 years and the workmen were handling 15-20 ton capacity dumpers as per statement of Autar Singh MW-1. Md. Jawed WW-1 dumper operator tried to prove that he had experience of more than 5 years as he was working since 1955 with small breakes in service, but he produced no certificate of such experience. Moreover experience is not the only pre-requisite qualification for being classified in Grade I. His statement about dumper capacity is quite vague and thus there is no evidence tha he was handling dumpers of atleast 22 tons capacity. What capacity machines, if any, were brought from N.C.D.C. remains only a matter of conjecture and such a vague statement cannot be relied upon in the face of defined statement of

Autar Singh MW-1 on the point of dumper capacity. These workmen were therefore rightly placed in grade II and were rightly given the wage scale of D Category i.e. the scale of Rs. 10.75-0.40-14.75.

9. **Dozer Operators**

Only one grade of Dozer Operators has been given with respect to the machanised working of N.C.D.C.(see page55). The job description of Dozer Operators demands that they should have atleast 5 years experience of handling atleast 150 Horse Power Dozers. The questions framed in the schedule of reference places burden on the workmen to prove that the wages did require revision. This means that the burden was upon the workmen to show that they fulfilled the requisite essentials of job description which may entitle them to B Category wages of operators. It is true that Evidence Act as such does not apply to industrial adjudication. However the principles of law enuntiated on the burden of prove and onus of proof being a basic principle of law the Industrial Tribunals are also required to follow the same. It was so held in **Ramendra Vs. 8th Industrial Tribunal 1975** Lab. I.C. 94 Calcutta. There is absolutely no evidence on either side on the point of experience of the dozer operators or of the horse powers of the dozers used in 4-B quarry. The only evidence is that admittedly the dozers are being used since 1964 and therefore on 15-8-67 the dozer operators had the experience of only 3 years. This fell short of the minimum required experience of the dozer operators for being classified in B Category. Learned Counsel for the management conceeded that because the dozer operators did not fit in the job description of B Category wages as given at page 55 they were placed one category below. The chart given in para 3 above will show that they were placed in the scale of Rs. 10.75-0.40-14.75 in line with dumper operators and were thus placed in D Category as given in para 14 of page 62Vol I of the Wage Board recommendations. According to the scheme of categorization it appears that if Grade I is placed in A category Grade II is placed in C Category as in the case of Excavator Operators. Similarly Drill Operator Grade I is placed in B Category and Drill Operator Grade II is placed in D Category. Excavating Plant Electrician Grade I has been placed in B Category and Grade II has been placed in D Category. Following that analogy the lower category of the dozer operator should get D category wages if the senior category of dozer operator is placed in B Category scale. This will further keep them in line with the drill operators. The past history indicates that dozer operators had similar wages as drill operators at the time of contractors and also when the wages were revised under the Wage Board scale. The management has thus rightly placed them in D Category in the scale of Rs. 10.75-0.40-14.75.

10. **Drill operators**

The job description of drill operator Grade I for getting B Category wages demands, not less than 5 years experience and the handling of the rotary blass drills of 7.7/8 inch diameter. Drill operator Grade II may have only 3 years exeperience and handling of the rotary/percussive drills used for quarry work. It is obvious that the drill operators in 4-B quarry had 3 years experience on 15-8-1967 and were handling the rotary or percussive drills for quarry work. They therefore answered the job description of drill operator Grade II. The burden was upon them for proving that they answered the job description of Grade I if they really wanted B Category wages. They have been rightly given D Category wages of Grade II in the scale of Rs. 10.75-0.40-14.75.

11. **Fitters**

The workmen crave for B Category wage scale of Excavating Plant Fitter Gr. I but that grade demands 7 years experience with ability to read and use instruments for accurate measurement and there should be capability to undertake the repair jobs independently. All this is not proved. Naturally these workmen were placed in Excavating Plant Fitter Gr. II in D Category scale of Rs. 10.75-0.40-14.75 as in the case of Motor Singh. Surat Singh Fitter appears to have been placed in Category V wages and Sukhdeo Chouhan in Category IV wages. They are not the new appointees. In fact appendix B to the failure report of the Asstt. Labour Commissioner goes to show that all these three fitters were appointed in 1964 and of them Sukhdeo Singh Chauhan was the senior most with reference to the date of his appointment. There is no obvious reason to discriminate one fitter from the other in the matter of emoluments so far as these three are concerned. It appears that their wages need revision so as to place them in D Category in the scale of Rs. 10.75-0.40-14.75 in order to bring them at per with Motor Singh.

12. **Abdul Mannan Mechanic**

Appendix B to the failure report of Asstt. Labour Commissioner would show that Abdul Mannan is a mechanic who was appointed on 1-4-1960. He was getting Rs. 327.00 per month basic at the time of reference in the grade of Rs. 12.00-0.60-18.00. It means that he has been placed in C Category as mentioned at page 62 of Wage Board recommendations Vol. I. In the year 1960 when he was appointed the working in the 4-B quarry had not been mechanised. His experience in mechanised working in fact started in 1964. In any case in the year 1968 he had not acquired the experience of 10 years which is the minimum required for Excavating Plant Mechanic Gr. I. He does not fit in the following job description of mechanic Gr.I as given on page 55 of Vol.II of Wage Board recommendations.

> "A highly skilled workman possessing a minimum 10 years experience in the repairs, maintenance and overhauling of shovels/draglines, Diesel Engines, Euclid/Let. Mach dumpers, tractors, dozers, etc. He should be capable of dismanting repairing and overhauling all types of diesel engines and assemblies. He should be capable of dismantling repairing and ctify them. He should undertake these jobs independently. He should be literate enough to maintain log books for repairs and maintenance and should understand the maintenance charts and spare parts lists."

The burden was upon the union to prove that he answered all these requirements of qualification and experience. It has failed to discharge that burden. He has therefore been rightly placed as mechanic Gr. II and has been rightly given C Category wage scale of Rs. 12.00-0.60-18.00. His wages therefore do not require any revision. Fitment to a grade/category of wage scale according to the job description does not amount to degradation to a lower wage structure.

13. **Dumpmen/Tripmen**

The union wants these workmen to be given the pay scale of Category V of daily rated workmen i.e. Rs. 7.95-0.28-10.75. The case of the management is that since their duties were much less than the duties of Munshis they were given Category III wages i.e. the scale of Rs.5.90-0.15.-7.40. Upward revision of wages of these workmen would cause unrest in other categories The last category of N.C.D.C. workmen (Excavation Section) where mechanised working is in vogue, is 'F' Category for which Category V wages have been recommended by the Wage Board. Mere saying that their job is less onerous as compared to Munshis is not sufficient comparative job requirements should have been produced giving specific reasons why it was necessary to depart from the wage Board recommendations for giving the wages of lower category. It is therefore obvious that Wage Board recommendations should prevail and the wages to these workmen should be revised so as to put them in Category V wage scale of Rs. 7.95-0.28-10.75.

14. So far as V.D.A. is concerned the management had no reason for not granting V.D.A. according to the price index as it rose from time to time. V.D.A. is part of the wage. The workmen are entitled to the difference between the regular rise or fall in V.D.A. as per six monthly revision of cost of living index and the V.D.A. that was actually paid to them.

15. It is therefore held that the wages of all the Excavation Plant Fitters should be brought in line in the scale of Rs. 10.75-0.40-14.75 with effect from 15-8-1967 and the arrears should be paid to them. The wages of the tripmen/dumpmen should be Category V wages with effect from 15-8-1967. Similarly the arrears of V.D.A. as it should have varied according to the cost of living index as against the money already paid under that head should be given to all the workmen and their V.D.A., should be brought to the level of the present cost of living index. The wages do require revision to this extent only. The reference is answered accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[F. No. 2/21/69—LR II-D.III. A]

S.O.1564.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Damoda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Karmatand (Via) Mohuda, Dist. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 19-4-1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

Reference No. 4 of 1975

(Ministry's Order No. L-2012/88/74-LR. II, dated 5-1-1975)
In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Damoda Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the Workmen—Shri J. D. Lal, Advocate.

State : Bihar. **Industry :** Coal.

AWARD

This reference was sent by the Government of India, Ministry of Labour to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed :—

"Whether the action of the management of Damoda colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited in dismissing from service Shri Jhagru Mahato and Shri Sita Ram Manjhi Miners, with effect from the 7th February, 1974 is justified? If not, to what relief is the workmen entitled ?"

The case of the workmen is that the two concerned workmen were issued charge-sheet dated 7-11-73 and 22-10-73 respectively for the alleged misconduct of absenting for more than 10 days without permission. The workmen concerned replied to the charge-sheet by their reply dated 8-11-73 and 23-10-73 respectively denying the charges and submitting that they and their family members were suffering from protracted illness and that they had informed the manager. A show of enquiry was held by Shri B. B. Singh, Personnel Officer who made the concerned workmen to put their L.T.I. on the prepared statement and they were denied all opportunities to defend themselves in the enquiry. The management dismissed the concerned workmen by their letter dated 7-2-74. It is alleged that in holding the enquiry the principles of natural justice were violated by the enquiry officer and the report of the enquiry officer was perverse and their dismissal unjustified.

The case of the management is that Ghagru Mahato was absenting himself from September, 1972 without any information on authorised leave and Sitaram Manjhi was absenting without any information or authorised leave from 28-5-73. Both of them were issued charge-sheet which they received. A departmental enquiry was held on 21-11-73 in which both the workmen were given all opportunities to cross-examine the witness of the management and defend themselves. The enquiry officer observed all the principles of natural justice. The concerned workmen were found guilty by the Enquiry Officer for their misconduct under the authority of the Standing Orders applicable to the colliery and accordingly they were dismissed.

As per the prayer of the parties I heard the matter on the preliminary issue as to the validity of the domestic enquiry held in this case. Where the workmen have been dismissed on the basis of finding in domestic enquiry, it is always open for the Tribunal to hear on the validity of the domestic enquiry.

Admittedly Jhagru Mahato was absenting for about a year and Sitaram Manjhi was absenting for about 5 months. The management for this long unauthorised absence of these two workmen issued them charge-sheet to which they replied. It is contended from the side of the workmen that there was only a show of enquiry and no proceedings were drawn up by the enquiry officer in the presence of the concerned workmen. Everything was prepared from before and they were made to put their L.T.I. on blank papers. This is denied from the side of the management whose case is that a proper enquiry was held in which all reasonable opportunities were given to the concerned workmen to defend their case. The workmen were given opportunities to cross-examine the witness examined by the management and to examine their own witnesses. Jhagru Mahato was examined as WW. 1 and Sitaram Manjhi was examined as WW. 2. WW. 1 says that he was called in the enquiry and he gave his thumb impression on blank papers. His statement was not recorded by Shri B. B. Singh, the enquiry officer. In the cross-examination this witness says that he does not remember if his statement was recorded and he did not call for any defence witness. WW. 2 Sitaram Manjhi says in his evidence that he received the enquiry notice and he attended the enquiry on the appointed date. His statement was not recorded and he gave his L.T.I. in four places. In his cross-examination he says that Bhubaneshwar Babu's statement was recorded and after Bhubaneshwar Babu signed he also put his L.T.I. He further says that he did not ask any question to Bhubaneshwar Babu and he also admits having given his statement before the enquiry officer. He also did not take any defence witness with him. So the WW. 2 in his cross-examination has substantially given a goby to his defence in this Reference. The learned Advocate appearing for the workmen pleads that WW. 2 is an illiterate workman and the Court should not put much importance on his cross-examination. Cross-examination of a witness is the test to verify the truth of otherwise of the evidence given by witness and there is no reason why I should over-look the cross-examination of WW. 2. The enquiry officer himself was examined as MW. 1 whose evidence is that the workmen were present in the enquiry and the statement of the witness were recorded in their presence in Hindi by the enquiry officer himself. The statements were explained to the concerned workmen in Hindi after which they put their L.T.I. His further evidence that he gave opportunity to the concerned workmen to cross-examine the witness examined by the management and also to examine their own witnesses. The enquiry proceedings are marked Ext. M1 and M1(a) and in the enquiry proceedings it appears that the signatures of the witnesses examined and L.T.I. of the concerned workmen were taken. Except oral evidence of the two concerned workmen there is nothing to show that there was only a show of enquiry in which the principles of natura justice were violated. The cross-examination of WW. 2 goes a long way to support the management's case that there was a proper enquiry. The proceedings of the enquiry officer as placed before me also shows that there was cross-examination of the management's witness by both the concerned workmen. There is nothing satisfactory before me to accept the workmen's case that there was no proper enquiry or that the principles of natural justice were violated. The next point for consideration is whether the findings of the enquiry officer was perverse. One man was absenting for one year and another man was absenting for 5 months. Not a scrap of paper has been filed to show that the workmen informed the authorities about the reason of their long absence or they prayed for any leave. There is also no satisfactory evidence from the side of the workmen about this. So the fact remains that Jhagru Mahato was absenting for about a year without notice and without any authority and Sitaram Manjhi was absenting for about 5 months without any notice or authority. In the reply to the charge-sheet they took the plea of their sickness and sickness in their

families. Certain hospital memos have been filed but they do not by themselves absolve the concerned workmen of all liability incurred for absence without notice. Clause 18(1) (n) of the Standing Orders denotes as misconduct-continuous absence without permission and without any satisfactory cause for more than 10 days for which demotion, dismissal without notice, fine and other penalties are provided. It is not denied before me that the Standing Orders do not apply in this particular case. The concerned workmen therefore come within the mischief of Clause 18(1) (n) of the Standing Orders. I should therefore find that in this case a proper domestic enquiry was held and the findings of the Enquiry Officer were not perverse. I may now see how far this Tribunal can invoke the powers given to it under S. 11A of the I.D. Act, which were brought into force from 15.12.71. The power of the Tribunal under the added section has been laid down in the case between the workmen of Firestone Tyre & Rubber Co Vs. their workmen as reported in 1973-I-LLJ 278/279 (S.C.).It is held therein that where the proper domestic enquiry was held, the Tribunal is now clothed with power under S.11A of the I.D. Act to reappraise the evidence in domestic enquiry and satisfy itself if the misconduct has been established by evidence at the domestic enquiry. In other works the Tribunal may hold that the misconduct is not established by the evidence in the domestic enquiry. The second power with which the Tribunal is now clothed is that the Tribunal can interfere with the punishment meeted out to a workman even when the misconduct against him is proved in a properly held enquiry. In other words the Tribunal may hold that the proved misconduct does not merit punishment by way of discharge or dismissal and it can under such circumstances award to the workman any lesser punishment instead. Jhagru Mahato it appears was a miner in the colliery for about 10 years and Sitaram Majhi was a miner in the colliery for 15 or 16 years. They are also illeterate which fact has not been denied by the company. They have absented for long without notice and have surely committed misconduct as defined in the Standing Orders. In the normal circumstances there was little reason for me to interfere with the punishment. Here it has not been shown to me that the concerned workmen had blamished record of service or they were warned or meted out with any punishment in the past. In clause 18 para IV of Standing Orders it is stipulated that in awarding the punishment under Standing Orders the authority awarding the punishment shall take into account the gravity of the misconduct, the previous record, other extenuating or aggravating circumstances that may exist There is nothing to show before me that in awarding this extreme punishment the authority took into account the other circumstances as mentioned therein. The offence lies in the fact that they were absent for a long time. I do not find any aggravating circumstances. As regards extenuating circumstances the only thing that can be said in favour of the concerned workmen is that they were literate, perhaps not knowing what is what. I have taken into consideration all aspect of the matter and my considered view is that a lesser punishment if awarded to the concerned workmen would meet the ends of justice especially when the misconduct is not like corruption, theft, drunkness, riotus, disorderly and indecent behaviour and things of the kind. Now in Clause 18(1) of the Standing Orders it is stipulated that for misconduct a workman may be suspended or fined or his increment may be stopped or he may be demoted or dismissed without notice Imposition of fine as provided in the Standing Orders as one of the punishments for misconduct would, in my opinion is a proper punishment in respect of the nature of misconduct committed by the concerned workmen. The fine to be imposed on the concerned workmen should be to the extent of half of the back wages due to them from the date of their dismissal from service till they are reinstated in the job. In other words the concerned workmen will be entitled to get half of their back wages due from the date of their dismissal to the date of their reinstatement and the other half back wages should be treated as fine imposed on them and paid by them. I may again state that this power I am exercising under Sec.11A of I.D.Act read with the decision of Supreme Court in the case between the workmen of Firestone Tyre & Rubber Co. Vs. their workmen as reported in 1973-I-LLJ 278/279 (S.C.)

In the result the action of the management of Damoda colliery of Messrs Bharat Cooking Coal Limited in dismissing from service Shri Jhagru Mahato and Shri Sita Ram Manjhi, Miners with effect from the 7th February, 1974 is not found justified in view of the facts and circumstances as stated by me earlier in my judgement. They should be reinstated in their job with effect from 7-2-1974 with continuity of service. The punishment of dismissal is reduced to a punishment of fine on the concerned workmen. The concerned workmen will be entitled to receive half of the back wages from 7.2.74 till the date of their reinstatement and the other half of the back wages is considered as fine imposed on the workmen, and the concerned workmen will not be entitled to receive the half portion of the back wages which is considered as fine imposed on them.

This is my award.

Dhanbad, dated the 14th April, 1976

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

[F. No. L-2012/88/74-LR-II-DIII. A]
R. P. NARULA, Under Secy.

New Delhi, the 24th April 1976

S.O. 1565.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sudamdih Project of M/s. National Coal Development Corporation Ltd., Post Office, Sudamdih, Dist. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th April, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, DHANBAD

In the matter of an industrial dispute under section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 24 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Sudamdih Project of Messrs National Coal Development Corporation Limited, Post Office Sudamdih (Dhanbad)..

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the Employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the Workmen—Shri D. Mukherjee, Advocate.

State : Bihar. Industry : Coal.

Dhanbad, the 15th April, 1976.

AWARD

The Central Government in the Department of Labour being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sudamdih Project of Messrs. National Coal Development Corporation, Post Office Sudamdih (Dhanbad) and their workmen by their order No. L-2012/67/73-LRII/DIII(A), dated 5th March, 1975, u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the same to this Tribunal for adjudication on the issues as specified in the Schedule below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Sudamdih Project of Messrs. National Coal Development Corporation Limited Post Office Sudamdih (Dhanbad) in removing from the rolls of the Colliery the name of Shri Pancham Prasad, General Mazdoor, in the month of February, 1971, is justified? If not to what relief is the workmen entitled?"

2. The case of the employers is that the concerned workman was a temporary attendant attached to the Assistant Engineer, Sudamdih Project of National Coal Development Corporation and he became traceless w.e.f. 7th February, 1971. The management was not aware of his whereabouts and they sent a letter to him on 1/2nd September, 1971 informing him that if he failed to join his duties within 7 days, his name will be struck off the rolls. The concerned workman did not turn up and so his services stand terminated. On 21-9-1971 a prisoner's petition was received by the employers from the concerned workman from District Jail Dhanbad in which he informed that he had been arrested on 7-2-1971 by the Police and that he would be joining his

post after his release on bail. By that time his services already stood terminated. The employers deny having received any letter dated 2nd June, 1971 from the concerned workman informing them about his arrest or asking leave. It is also alleged that the reference is incompetent in that the appropriate Government refused to make any reference in the first instance and the matter closed but all on a sudden on 27-7-1973 a letter was received and a reference was made. This the appropriate Government cannot do.

3. The case of the workman is that the concerned workman was arrested by the Dhanbad Police on 7-2-1971 and he was detained in Jail custody upto 5-7-1972. While in the jail custody he had sent a letter on 2-6-1971 to the management informing them about his detention and also praying for leave to which no reply was received. Knowing everything the management sent a letter dated 1-9-1971 to his home address asking him to join within 7 days. He was refused employment when he came to join his duties on 6-2-1972 after his release. He was not at all responsible for his absence as it was beyond his control. Removal from the rolls is against the provision of Standing Orders. On the law point it is asserted that the Reference is quite competent.

4. I take up the law point first. After the failure of conciliation, the appropriate Government by their letter dated 27-7-73 refused to make any reference as they felt that it was not fit for reference to an Industrial Tribunal. Later, however, on 5-3-1975 the appropriate Government referred the industrial dispute to the Tribunal for adjudication. It is submitted after the appropriate Government refused to make any reference of the industrial dispute on 27-7-1973, they have no jurisdiction to make a fresh reference. So the reference is incompetent. I cannot accept the contention of the employers. And order of the Government U/s. 10(1) of the Industrial disputes Act is not judicial or quasi-judicial order and there is no finality about it. The consensus of judicial opinion is that a prior order by the Government refusing to refer for adjudication a particular dispute can not affect the jurisdiction of the Government to exercise the statutory power conferred upon it by Section 10(1) of the Act on any subsequent occassion. It follows that even if at one stage the Government had come to the conclusion that no reference was called for, it may re-examine the matter, whether in the light of fresh material or otherwise, and make a reference if it comes to the conclusion that a reference is justified in the interest of industrial peace. Hence the Government can always reviewed its previous decision and make a reference. If any authority is needed I may quote—(1) State of Madras Vs. C. P. Sarthy—. (1953) (I) L.L.J. 174 (S.C.) (2) Radhakrishna Mills Ltd., Vs. State of Madras-(1956) (I) L.L.J. 221 (Madras High Court) (3) Rawalpindi State Transport Company Vs. State of Punjab-1964 (I) L.L.J. 644 (Punjab High Court) (4) State of Bombay Vs. Krishna (1960) (II) L.L.J. 592 (S.C.) (5) Shankar Flour, Rice and Dal Mills Vs. Labour Court (1966) (I) L.L.J. 807 So I am to hold that the present reference of the industrial dispute to the Tribunal is competent.

5. The fact remains that the concerned workman arrested by the police on 7-2-1971 and he was in jail custody till 5-7-1972. So he could not join his duties till release. The workman claims to have sent a letter dated 2-6-71 to the Manager, through the Jail Superintendent, Dhanbad intimating them about his arrest and praying for leave. This is denied by the management. In support of their case the workman files a certificate from the Jail Superintendent, Dhanbad which is marked Ext. W-1. The only objection against this document as pressed by the advocate representing the employers is that this certificate was subsequently procured by the workman, on consideration and he puts a suggestion like that in the cross-examination of the workman. In support of his contention Shri Choudhury refers to the letter of the concerned workman (Ext. M-1). It is submitted that the letter itself will show that the concerned workman never sent any other letter to the employers any time before not to speak of 2-6-1971. It is true that in Ext. M-1 the workman did not mention anything about his alleged earlier letter dated 2-6-1971. But that is duly a circumstance but not anything conclusive. Shri S. L. Kaswani, Deputy Personnel Manager of Central Jharia was examined as MW-1. His evidence is that there was a receipt clerk who used to receive letters from outside. MW-1 made enquiries from this register regarding receipt of this letter but nothing like that was found. The receipt register has not of course been filed, which would have been a good piece of evidence of the concerned workman also remain in this Jail Superintendent, the issue of which is not denied. The evidence of the concerned workman also remains in this respect. The circumstances are not satisfactory in favour of holding that Ext. W-1 was subsequently procured and that too on consideration. There is therefore no reason why Ext. W-1 should not be accepted and relied upon. On such reliance the fact boils down to this that on 2-6-1971 the concerned workman sent a letter from Jail informing the management about his arrest by the Police and praying for leave till his release on bail. Shri T. P. Choudhury, advocate for the employers in his usual fairness submits that if the Court accepts the plea of the workman about the letter dated 2-6-1971 (Ext. W-1), then the management was wrong in terminating his services in September, 1971. So it may at once be said that when the Tribunal is inclined to believe the evidence of WW-1 about his letter to the management dated 2-6-1971, the management was wrong to retrench him after this. His tention in Jail on arrest by the Police is a matter which is beyond the control of the concerned workman. I may deal with the matter in another aspect. The employers sent a letter dated 1/2nd September, 1971 to the concerned workman in his village home address in the district of Banaras. The workman was in Jail in Dhanbad at that time. There is nothing to show that the letter Ext. M-3 was actually served on or refused by the workman. If there was no service of Ext. M-3 on the workman, he could not be expected to join within 7 days as asked by the employers. When there was no service of Ext. M-3 on the concerned workman, the management cannot be said to have acted fairly to terminate his services on the presumption that Ext. M-3 was served on the concerned workman. Admittedly the concerned workman sent a letter from prison to the management on 18-9-1971 (Ext. M-1), that is only a few days after the management's letter dated 1/2nd September, 1971. From the employers side All India Services Law Journal Vol. III, No. 1 page 18 was placed. The facts are different. That was with regard to notice under article 311 of the constitution meant for Public servants. There the employer had given several chances to the employee asking him to explain his conduct of absence but he did not care to reply to them. That is not the case here as already discussed. It is a case of involuntary absence due to causes beyond the control of the workman. The Standing Orders of the company have not been placed to show the limitation on leave, I may refer to the judgment in 1976 Labour & Industrial Cases, 1976 January Vol. 9 page 21 and page 25—Delhi Cloth & General Mills Vs. Piare Lal, Delhi High Court which is as follows :—

"It would not be reasonable for the management to decline leave to a workman to the extent necessary where his absence from work is due to any cause beyond his control and when it is possible to grant leave without pay". Now such being the case here the management could have granted him leave without pay to the extent necessary. On the facts accepted by me, it is not a case of deserting job so as to lead to his automatic termination of service without notice. I should therefore find that in the circumstances of the case, the management was not justified to remove the name of the concerned workman from the rolls of the colliery which amounts to terminating his service.

6. In the result, my finding is that the action of the management of Sudamdih Project of Messrs. National Coal Development Corporation Limited is not justified in removing the name of the concerned workman from the rolls of the Colliery in the month of February, 1971. The concerned workman should therefore be reinstated in his job with continuity of service. With regard to back wages, the workman is entitled to get back wages only for the period for which he is entitled to it according to the Standing Orders or Rules of the Company. The period for which he is not entitled to back wages should be treated as leave without pay.

This is my award.

K. K. SARKAR, Presiding Officer

[F. No. L-2012/67/73-LR II/D-III-A]

R. P. NARULA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.